हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 265 बेमेतरा, शुक्रवार 22 मई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

बेंगलुरु नगर निगमों के चुनाव अब 31 अगस्त तक कराए जाएंगे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के पांच नगर निगमों में चुनाव पूरा करने के लिए डेडलाइन बढ़ी दी. अब कर्नाटक सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को 31 अगस्त तक चुनाव कराना होगा. इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने की. वरिष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी ने कर्नाटक सरकार की तरफ से अदालत में पैरवी है. सिंघवी ने कहा कि एसआईआर अभ्यास की वजह से राज्य सरकार को स्टाफ का इंतजाम करने में मुश्किल हो रही है. सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने पिछली डेडलाइन 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2026 कर दी. राज्य सरकार और एसईसी ने नगर निगम चुनावों के लिए तीन महीने का और समय देने की अर्जी दी थी. दलील दी गई कि राज्य के कर्मचारी जनगणना, वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने में व्यस्त हैं. इस आधार पर राज्य और एसईसी ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जनवरी के आदेश में बदलाव की मांग की, जिसमें 30 जून तक नगर निगम चुनाव पूरे करने का निर्देश दिया गया था. वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर ने समय-सीमा बढ़ाने की दलीलों का विरोध किया. परमेश्वर ने कहा कि पिछली बार यह वादा करने के बाद समय-सीमा बढ़ाई गई थी कि चुनाव 30 जून, 2026 तक करवा लिए जाएंगे.

महिगवां में पेट्रोल पम्प पर देर रात लूट, चौकीदार से मारपीट

लखनऊ। महिगवां थाना क्षेत्र में स्थित एक पेट्रोल पम्प पर देर रात लूट की घटना सामने आई है। बैटरी रिक्शा से पहुंचे अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल पम्प से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया। विरोध करने पर पम्प पर मौजूद चौकीदार के साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया गया है।पुलिस के अनुसार, यह घटना 19 मई 2026 की रात करीब एक बजे की है। थाना महिगवां क्षेत्र के ग्राम सिंहपुर निवासी ऋषि यादव ने थाना महिगवां में तहरीर देकर बताया।

पीओके में अज्ञात हमलावर ने गोली मारी

पुलवामा आतंकी हमले के मास्टर माइंड हमजा बुरहान की हत्या

नई दिल्ली/ एजेंसी

इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की हत्या कर दी गई है। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और तिर्बंधित संगठन 'अल बद्र' के प्रमुख कमांडर आतंकी हमजा बुरहान को पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में अज्ञात हमलावर ने गोली मारी। हमले में आतंकी हमजा बुरहान की मौत हो गई है। हमजा बुरहान की हत्या के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पुलवामा का रहने वाला यह मोस्ट वांटेड आतंकी पिछले 7 सालों से पाकिस्तान में रह रहा था। सूत्रों के मुताबिक ओके में अज्ञात हमलावरों ने हमजा बुरहान को निशाना बनाकर कई गोलियां चलाईं। हमले के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भारत सरकार ने 2022 में हमजा बुरहान को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया था। पुलवामा आतंकी हमला भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक और भीषण आतंकवादी हमलों में से एक है, जो 14 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के लेथपोरा में हुआ था। इस आत्मघाती आतंकी हमले में भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ के लगभग 2,500 जवान 78 वाहनों के काफ्लि में जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। दोपहर करीब 3:15 बजे, विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने जवानों को ले जा रही बस में टक्कर मार

दी। कार में करीब 300 किलोग्राम से अधिक आरडीएक्स और अन्य विस्फोटक भरे हुए थे। टक्कर होते ही एक भयानक धमाका हुआ, जिससे बस पूरी तरह नष्ट हो गई। इस हमले को स्थानीय कश्मीरी आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार ने अंजाम दिया था। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन बालाकोट अंजाम दिया था। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के अड्डे को तबाह कर दिया था। हमजा बुरहान पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं में शामिल था। वह खुद को पाकिस्तान में टीचर बताता था। साथ ही 2019 के बाद से कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा था। वह पीओके के इलाके में कई आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग दे रहा था। साथ ही बॉर्डर इलाके में वह आतंकियों को घुसपैठ कराने में मदद करता था।

कौन है हमजा बुरहान?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुरहान का असली नाम अर्जुमंद गुलजार डार है। हमजा बुरहान पुलवामा के रत्नीपोरा का रहने वाला था। 2017 में पाकिस्तान जाकर हमजा आतंकवादी संगठन अल बद्र में शामिल हो गया। अल बद्र को भारत में एक आतंकवादी संगठन के तौर पर लिस्ट किया गया है हमजा अल बद्र के कमांडर के तौर पर काम कर रहा था।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया आतंकी हमजा बुरहान की हत्या की ली जिम्मेदारी

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में मारे गए पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की हत्या की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े टायसन बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी हत्या का दावा किया है। हालांकि, नवभारत लाइव इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि हमजा पर पुलवामा में आतंकी हमले का आरोप था। यह भारत के सबसे घातक हमलों में से एक था। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफजवानों के काफ्लि पर आईईडी से हमला किया गया था। इस हमले में लेथपोरा क्षेत्र में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे वाहन के साथ बस को टक्कर मार दी थी, जिसमें सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे।

कबीर ने सीएम सुवेंदु को चेतावनी दी

गाय की कुर्बानी देने से मुसलमान को कोई नहीं रोक सकता-हुमायूं

कोलकाता/ एजेंसी

ईद उल-अज़हा यानी बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत गरमा गई है। आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख और विधायक हुमायूं कबीर के बयान ने बंगाल के राजनीतिक तापमान को गरमा दिया है। हुमायूं कबीर ने सीएम सुवेंदु अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि गाय की कुर्बानी देने से मुसलमान को कोई नहीं रोक सकता। हुमायूं कबीर ने कहा कि कुर्बानी तो 1400 साल पहले से हो रही है और जब तक दुनिया रहेगी, तब तक कुर्बानी होती रहेगी। उन्होंने सीएम सुवेंदु

अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि आग से मत खेलो। दरअसल पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार ने हाल ही में 'वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950' के तहत एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। इसके तहत फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना गाय और भैंस की हत्या पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि बिना प्रमाण पत्र के किसी भी बैल, बछड़े, गाय या भैंस को मारा नहीं किया जा सकता। 27 मई को बकरीद से पहले सरकार ने यह नोटिस जारी किया है। बंगाल की बीजेपी सरकार के इस फैसले के बाद नया विवाद शुरू हो गया है। इस नोटिस पर एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर ने सरकार को सीधी चुनौती दी है। हुमायूं कबीर ने कहा कि कुर्बानी तो 1400 साल पहले से हो रही है और जब तक दुनिया रहेगी। तब तक कुर्बानी होती रहेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कोई भी कुर्बानी को नहीं रोक सकता है।

सेना के टेंडर घोटाले में फोर्ट विलियम में तैनात कर्नल गिरफ्तार

कोलकाता। देश की रक्षा की शपथ खाने वाले एक कर्नल के करतूतों की सीबीआई ने जब आज उजागर किया तो सबकी आंखें फटी रह गई। जी हां, महानगर कोलकाता स्थित सेना मुख्यालय फोर्ट विलियम से जुड़े कथित 50 लाख घूसकांड में सीबीआई ने आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के कर्नल हिमांशु बाली को गिरफ्तार किया है। केन्द्रीय एजेंसी का आरोप है कि सेना के टेंडर, बिल पास कराने और घटिया सैंपल मंजूर करने के बदले रिश्वत ली गई। मामले में कानपुर की कंपनी ईस्टर्न ग्लोबल लिमिटेड और कारोबारी अक्षत अग्रवाल को भी आरोपी बनाया गया है। सीबीआई के अनुसार रिश्वत की रकम हवाला चैनल के जरिए दिल्ली भेजी जानी थी।

दिल्लीवालों को रेखा सरकार का तोहफा

अब 1.20 लाख आय वाले भी बनवा सकेंगे राशन कार्ड-रेखा

नई दिल्ली/ एजेंसी

दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों और नए लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने 7 लाख 71 हजार 384 अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए हैं, ताकि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 13 वर्षों से राजधानी में गरीबों के नए राशन कार्ड नहीं बनाए गए, जिससे जरूरतमंद लोग दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर थे। अब सरकार ने डिजिटल प्रक्रिया के जरिए नए राशन कार्ड बनाने की शुरुआत कर

दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय विजन के तहत कराए गए ऑडिट में पता चला कि करीब 1 लाख 44 हजार लोग ऐसे थे, जिनकी आय तय मानकों से ज्यादा थी। इसके बाद सरकार ने 7 लाख 71 हजार 384 अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए हैं, ताकि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। सीएम ने कहा कि 15 मई से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित होगी। राशन वितरण भी बायोमेट्रिक तरीके से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और सही व्यक्ति तक पूरा राशन पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में फूड सिक्योरिटी रूल 2013 को अब पूरी तरह लागू कर दिया गया है। लोग अपने घर के पास स्थित सुविधा केंद्रों पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में

अभिषेक बनर्जी को दी बड़ी राहत देश नहीं छोड़ सकते....

नई दिल्ली। कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है। दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट का यह फैसला चुनाव रैलियों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में आया है. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि बनर्जी देश छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं. हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 31 जुलाई तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया है. टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज एफआईआर मामले में कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी है. गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया है ।

पुणे के एक अपार्टमेंट की लिफ्ट में फंसने से 7 साल के बच्चे की मौत

पुणे । शहर की एक सोसायटी में लिफ्ट में फंस जाने से सात साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आाया है. बताया जाता है कि शहर के सिंहगढ़ रोड इलाके में निंबज नगर के रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में यह घटना हुई. मृतक लड़के की पहचान शिवांश शैलेश धुत (उम्र 7) के रूप में हुई है. यह घटना मंगलवार (19 मई) को रात लगभग 10:30 बजे हुई बताई गई है. इस मामले में सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है. इस घटना के बारे में और जानकारी से पता चलता है कि मंगलवार रात करीब 10:30 बजे, सिंहगढ़ रोड इलाके में।

रायपुर एयरपोर्ट में बड़ा हादसा

सीलिंग रिपेयरिंग के दौरान 30 फीट की ऊंचाई से गिरा इलेक्ट्रीशियन,इलाज के दौरान हुई मौत

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में आज बड़ा हादसा हुआ है, जहां एयरपोर्ट परिसर में सीलिंग रिपेयरिंग के दौरान एक इलेक्ट्रीशियन की 30 फीट की ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई है। घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में हड़कंम मच गया है। यह घटना माना थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान कुबेर कुमार साहू (32) के रूप में हुई है, जो कि दुर्ग जिले के जाम गांव का रहने वाला था। आज कुबेर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में सीलिंग

रिपेयरिंग का काम कर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो 30 फीट की ऊंचाई से गिर गया। घटना के बाद एयरपोर्ट स्टाफ और मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे माना के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इलेक्ट्रीशियन बिना सेफ्टी बेल्ट और सुरक्षा उपकरण के काम कर रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। घटना के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगा है। माना थाना सीएसपी लंबोधर पटेल ने बताया की स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट टर्मिनल में इलेक्ट्रिशियन कर्मचारी मेंटेनेंस कार्य के दौरान गिर गया था, जिसे गंभीर अवस्था में माना स्थित अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान डॉक्टर ने कर्मचारी को मृत घोषित कर दिया है. पूरे प्रकरण पर मर्ग कायम कर जाँच की जा रही है। सभी बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया की मेंटेनेंस कार्य के दौरान कर्मचारी गिरकर घायल हो गया था, जिसे तत्काल उपचार के लिए माना स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस को पूरे घटनाक्रम की सूचना दी गई है।

इबोला वायरस का अफ्रीका में कहर

सैकड़ों लोगों की मौत के बाद मोदी सरकार का अलर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए एडवाइजरी जारी की...

नई दिल्ली/ एजेंसी

इबोला वायरस ने अफ्रीका में कहर मचाकर रखा हुआ है। इस वायरस से सेंट्रल अफ्रीका में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 1000 से ज़्यादा सस्पेक्टेड केस हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफकांगो और युगांडा में फैले इबोला को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। अफ्रीका में इबोला वायरस के कहर को देखते हुए मोदी सरकार ने अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को एडवाइजरी भेजी है। पूरे मामले पर मोदी सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। DGHS ने सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को एडवाइजरी भेजी है खासकर उन यात्रियों के लिए जो घ्नक्रकांगो, युगांडा और साउथ सूडान जैसे हाई रिस्क देशों से आ रहे हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर किसी यात्री में बुखार, सिरदर्द, कमजोरी, उल्टी-दस्त, गले में खराश या खून बहने जैसे लक्षण दिखते हैं तो उसे इमिग्रेशन से पहले ही एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर को रिपोर्ट करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम और अन्य संबंधित विभागों ने स्थिति की

समीक्षा की है और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भारत में फ्लिहाल इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है और देश के लिए वर्तमान खतरा बेहद कम है। हालांकि सावधानी के तौर पर निगरानी और तैयारियों को और मजबूत किया जा रहा है। इबोला एक बेहद खतरनाक बीमारी है इसलिए केंद्र सरकार ने यात्रियों से हेल्थ स्क्रीनिंग में पूरा सहयोग करने की अपील की है। एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित मरीज के खून या बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आया है तो उस पर भी नजर रखी जाए। भारत आने के बाद 21 दिनों के अंदर अगर लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताएं।

ईरान जंग पर ट्रम्प-नेतन्याहू आपस में भिड़े

इजराइल हमला चाहता है,अमेरिका का डील...

ईरान। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। 'सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमले जारी रहें, जबकि ट्रम्प फ्लिहाल बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि नेतन्याहू ने ट्रम्प से कहा कि ईरान पर प्रस्तावित हमले रोकना गलती है और सैन्य कार्रवाई जारी रहनी

चाहिए। खबर के अनुसार नेतन्याहू को समझौते को लेकर संशय है और उनका मानना है कि ईरान की सैन्य ताकत को और कमजोर करने के लिए युद्ध फ्रि से शुरू करना चाहिए, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि समझौते की संभावना बनी हुई है.

सीसी सड़क बनी भ्रष्टाचार की भेंट, गुणवत्ता विहीन निर्माण पर ग्रामीणों में आक्रोश

जगदलपुर/मूक पत्रिका

पवन कुमार नाग बस्तर -जगदलपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत अलनार के आश्रित ग्राम केशबोपारा में निर्माणाधीन सीसी सड़क इन दिनों ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार और गुणवत्ता विहीन कार्य किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में नियमों और मापदंडों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार सड़क निर्माण में मोटाई और चौड़ाई दोनों में कमी की जा रही है। ऊपर से सड़क को मजबूत और मोटा दिखाने के लिए दोनों किनारों पर लगाए गए लगभग 8 इंच के फ्लाई प्रॉम को करीब 2 से 3 इंच तक जमीन के अंदर गाड़ दिया गया है। इससे सड़क ऊपर से देखने पर 8 इंच मोटी दिखाई देती है, लेकिन अंदरूनी हिस्से में वास्तविक मोटाई केवल 5 से 6 इंच ही रह जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस तरह की अनियमितता कर ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पंचायत स्तर पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि विभागीय अधिकारी समय-समय पर निर्माण स्थल का सही तरीके से निरीक्षण करते, तो विकास कार्यों की गुणवत्ता बनी रहती और ग्रामीणों को घटिया निर्माण कार्य का सामना नहीं करना पड़ता। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि शासन द्वारा गांवों के विकास के लिए लाखों रुपए स्वीकृत किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य कर राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वाले सरपंच, सचिव तथा संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे मामलों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्य केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहेंगे और जनता को सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।

सांभर शिकार मामले में 8 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए, लेकिन वन विभाग की चुप्पी पर उठे सवाल..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

वन परिक्षेत्र सारंगढ़ सामान्य अंतर्गत मेकरा परिसर में सांभर के अवैध शिकार मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले के मुख्य आरोपी देवनाथ नायक वल्द जीतराम नायक समेत कुल 8 आरोपियों को 18 मई 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी आरोपियों को 30 मई 2026 तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामला वन्यजीव शिकार से जुड़ा होने के कारण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अब तक विभाग की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक मेकरा परिसर क्षेत्र में सांभर के अवैध शिकार की सूचना के बाद वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा था। हालांकि पूरे मामले में विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और सूत्रों का कहना है कि यदि मामला इतना गंभीर है तो वन विभाग द्वारा अब तक प्रेस विज्ञप्ति या आधिकारिक बयान जारी क्यों नहीं किया गया। वन्यजीव संरक्षण को लेकर बड़े-बड़े दावे करने वाला विभाग इस मामले में असामान्य चुप्पी साधे हुए है।

मामले को दबाने की कोशिश के आरोप-क्षेत्र में चर्चा है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों का दावा है कि कार्रवाई तो की गई, लेकिन पूरे घटनाक्रम को सार्वजनिक करने से बचा जा रहा है।

इससे यह आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं न कहीं मामले की गंभीरता को कम दिखाने का प्रयास हो रहा है। वन विभाग की ओर से न तो जब्त सामग्री की जानकारी दी गई है और न ही शिकार की पूरी परिस्थितियों को लेकर कोई खुलासा किया गया है। इससे लोगों के बीच संदेह और बढ़ गया है।

वन्यजीव संरक्षण के दावों पर सवाल-वन विभाग लगातार वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता बचाने की बात करता है, लेकिन इस तरह के गंभीर मामलों में पारदर्शिता की कमी विभाग की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। लोगों का कहना है कि यदि विभाग सच में वन्यजीव संरक्षण को लेकर गंभीर है तो ऐसे मामलों में खुलकर जानकारी सामने आनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। फिलहाल पूरे मामले में विभागीय चुप्पी और आधिकारिक बयान का अभाव कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चांपा ने श्रद्धा से मनाया स्व. राजीव गांधी का शहादत दिवस

चांपा/मूक पत्रिका

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चांपा द्वारा भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेसजनों ने स्व. राजीव गांधी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।कार्यक्रम की शुरुआत जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश अग्रवाल द्वारा स्व. राजीव गांधी के तैलचित्र पर दीप-प्रज्वलन से हुई। उन्होंने अपने संबोधन में स्व. राजीव गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश ने एक दूरदर्शी और युवा प्रधानमंत्री को खोया है, जिसकी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया।जिला महामंत्री नागेंद्र गुप्ता ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध मजबूती से खड़े रहने की बात कही और उपस्थित कांग्रेसजनों को इसके खिलाफ शपथ दिलाई।

कार्यक्रम का संचालन कर रहे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील साधवानी ने सभी से दो मिनट का मौन रखवाकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कराई, इसके पश्चात कार्यक्रम के समापन की घोषणा की गई। शहादत दिवस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, ब्लॉक अध्यक्ष सुनील साधवानी, उपाध्यक्ष किशन सोनी, महामंत्री नागेंद्र गुप्ता, मंडल अध्यक्ष अनिल मोदी, राज सरोज, वरिष्ठ कांग्रेसी उमेश तिवारी, ब्लॉक उपाध्यक्ष हरीश श्रीवास, भालचंद्र तिवारी, रामबाई स्वर्णकार, माणिक मसीह, गुलशन सोनी, ब्लॉक महामंत्री रंजन कैवर्त, अनिल बनकर, व्यापार प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष राज अग्रवाल, पार्षद अंजली देवांगन, पार्षद पवन साहू, पार्षद दुर्गा कुर्रे, पार्षद पवन आर्य, ब्लॉक सचिव जीवन बंजारे, सेक्टर प्रभारी संजय देवांगन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

माओवाद प्रभावित गांवों के बच्चों ने मांगा स्कूल भवन, कलेक्टर ने दिया आश्वासन

एक्सपोजर विजिट में बच्चों ने देखी शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। माओवाद प्रभावित उसूर ब्लॉक के पुजारी कांकेर, गलगम और मारूडबाका गांवों के बच्चों के लिए आयोजित विशेष एक्सपोजर विजिट के दौरान बच्चों ने स्कूल भवन की मांग रखी, जिस पर कलेक्टर श्री विश्वदीप ने आश्वासन दिया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों से परिचित कराना तथा उनमें सकारात्मक सोच विकसित करना था।भ्रमण के दौरान बच्चों ने ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी पहुंचकर जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय और 'छू लो आसमान' संस्थान का अवलोकन किया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और भविष्य निर्माण के संबंध में जानकारी दी। बच्चों ने सेंट्रल लाइब्रेरी का भी भ्रमण किया और अध्ययन संसाधनों को देखा।इसके बाद बच्चों को कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत और जिला चिकित्सालय ले जाया गया। यहां उन्हें जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड निर्माण, पंचायती राज व्यवस्था तथा अस्पताल की ओपीडी, ब्लड बैंक और एक्स-रे कक्ष की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। कलेक्टर विश्वदीप ने बच्चों से आत्मीय बातचीत की और गर्मी को देखते हुए उनके लिए कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था कराई। बातचीत के दौरान बच्चों ने बताया कि उनके गांव में अब भी झोपड़ी में स्कूल संचालित हो रहा है। इस पर कलेक्टर ने कहा कि स्कूल भवन का निर्माण जल्द कराया जाएगा। बच्चों ने स्कूल ड्रेस, टाई, जूते और मोजे की मांग भी रखी, जिस पर कलेक्टर ने आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।संवाद के दौरान जब कलेक्टर ने बच्चों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी फिल्म देखी है, तो बच्चों ने नकारात्मक जवाब दिया। इसके बाद कलेक्टर ने बच्चों के लिए प्रेरणादायी फिल्म का विशेष प्रदर्शन कराने के निर्देश दिए।कार्यक्रम में डीईओ लखनलाल धनेलिया, एपीसी जाकिर खान, संकुल समन्वयक और शिक्षादूत मौजूद थे।

मौहापाली में खनिज विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप, कार्रवाई पर उठे सवाल

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

गुरुवार सुबह सरिया तहसील क्षेत्र के मौहापाली में खनिज विभाग की अचानक हुई छापेमारी से अवैध खदान संचालकों में हड़कंप मच गया। सुबह-सुबह विभाग की टीम के पहुंचते ही इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मौके पर कई वाहन और मशीनें मौजूद थीं, जिनका उपयोग अवैध डोलोमाइट उत्खनन में किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि विभाग ने एक भारी जेसीबी मशीन को जब्त किया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि छापेमारी के दौरान मौके पर कुल पांच गाड़ियां पकड़ी गई थीं, लेकिन कार्रवाई केवल एक वाहन पर की गई। बाकी वाहनों को कथित तौर पर लेनदेन के बाद छोड़ दिए जाने की चर्चा क्षेत्र में जोर पकड़ रही है। हालांकि इस मामले में विभाग की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लोगों का कहना है कि यदि मौके पर अवैध उत्खनन हो रहा था तो फिर बाकी वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इससे पूरी कार्रवाई की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं।

अवैध खदानों पर नहीं हुई सीलिंग कार्रवाई

कार्रवाई को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि जिन स्थानों पर छापेमारी की गई, वहां संचालित खदानें कथित तौर पर अवैध बताई जा रही हैं, लेकिन खदानों को सील करने जैसी सख्त कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि खदानें नियमों के खिलाफ संचालित हो रही थीं तो उन्हें तत्काल बंद कर सील किया जाना चाहिए था। इससे यह चर्चा भी तेज हो गई है कि जिले में अवैध खनन का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है और कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है।

कई गांवों में लंबे समय से जारी है अवैध उत्खनन

जानकारी के अनुसार सरिया तहसील क्षेत्र के कटंगपाली, मौहापाली, जोतपुर, छैलफेरा, नौघटा, बिलाईगढ़, छूहीपाली सहित कई गांवों में लंबे समय से अवैध डोलोमाइट पत्थर का उत्खनन और परिवहन खुलेआम जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई क्रेशर बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहे हैं, जबकि कुछ की लीज और लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बावजूद काम जारी है। इसके अलावा भंडारण क्षमता से ज्यादा क्रशिंग किए जाने की भी शिकायतें सामने आती रही हैं।

खनिज विभाग और टास्क फोर्स की भूमिका पर उठे सवाल

लगातार सामने आ रही शिकायतों और अवैध उत्खनन के बावजूद खनिज विभाग और जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में आ गई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि नियमित और निष्पक्ष कार्रवाई होती तो अवैध खदानों का संचालन इतने लंबे समय तक खुलेआम नहीं चलता। लोगों का आरोप है कि कार्रवाई केवल दिखावे तक सीमित रहती है, जबकि बड़े स्तर पर चल रहे अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर टास्क फोर्स और जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों की निगरानी के बावजूद अवैध खनन का यह खेल किसके संरक्षण में जारी है।

सरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई : दो दिनों में 38 किलो से अधिक गांजा जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार; उड़ीसा से जशपुर-धरमजयगढ़ तक फैला था नेटवर्क..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

सरिया थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में कुल 38 किलो 150 ग्राम से अधिक गांजा जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में पुलिस ने कार और मोटरसाइकल समेत लाखों रुपये के वाहन भी जब्त किए हैं। दोनों मामलों में आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में बिक्री करने की फिराक में थे।

कंचनपुर बेरियर में कार से 30 किलो 835 ग्राम गांजा जब्त

पहली कार्रवाई 19 मई 2026 को ग्राम कंचनपुर बेरियर मेन रोड के पास की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उड़ीसा से एक सफेद रंग की स्वीफ्ट डिजायर कार में भारी मात्रा में गांजा लाया जा रहा है और उसके आगे एक अन्य डिजायर कार पायलटिंग कर रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों वाहनों को रोका। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम बबलू चौहान निवासी जशपुर, दिलशाद अंसारी निवासी

पत्थलगांव और बलदेव यादव निवासी लैलूंगा बताया। तलाशी लेने पर स्वीफ्ट डिजायर कार से 30 पैकेटों में भरा 30 किलो 835 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस जांच में आरोपियों ने पूछताछ के दौरान उड़ीसा के बौद्ध क्षेत्र से गांजा खरीदकर जशपुर और पत्थलगांव क्षेत्र में बिक्री करने की योजना स्वीकार की। मामले में दो कार, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री सहित करीब 18 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है।

थाना सरिया के सामने बाइक सवार से 8 किलो 315 ग्राम गांजा बरामद

दूसरी कार्रवाई 20 मई की रात थाना सरिया के सामने मेन रोड पर की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि उड़ीसा की ओर से एक व्यक्ति टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल में गांजा लेकर रायगढ़-धरमजयगढ़ की ओर जा रहा है। मुखबिर सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक सवार रवि प्रसाद सिदार निवासी धरमजयगढ़ को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास रखे नीले रंग के बैग से 8 पैकेटों में भरा 8 किलो 315 ग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी ने पूछताछ में उड़ीसा के सोनपुर-बौद्ध क्षेत्र से गांजा खरीदकर छोटे-छोटे पैकेट बनाकर बिक्री करने की बात स्वीकार की।

मामले में पुलिस ने करीब 80 हजार रुपये कीमत का गांजा और 1.50 लाख रुपये कीमत की टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपी के खिलाफ धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

उड़ीसा से छत्तीसगढ़ तक सक्रिय गांजा तस्करी नेटवर्क पर पुलिस की नजर

लगातार दो दिनों में हुई इन कार्रवाइयों से यह साफ हो गया है कि उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों तक गांजा तस्करी का नेटवर्क सक्रिय है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आगे की विवेचना की जा रही है।

जनता से सीधा संवाद कर मंत्री ने कहा — शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता

सुशासन तिहार 2026 : कटई में लगा जन समस्या निवारण शिविर, विभिन्न योजनाओं से हितग्राही हुए लाभान्वित

अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश, समस्याओं के त्वरित निराकरण पर दिया जोर, मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर बढ़ाया उत्साह

बेमेतरा/मूक पत्रिका

सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम पंचायत कटई स्थित शासकीय हाई स्कूल मैदान परिसर में आज विशाल जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति में आयोजित शिविर में आम नागरिकों ने अपनी समस्याएं एवं मांगें प्रशासन के समक्ष रखीं, जिनका यथासंभव मौके पर ही निराकरण किया गया। ग्रामीणों में शिविर को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों में लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को तत्काल लाभ भी प्रदान किया गया।

विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल, हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ-शिविर में खाद्य विभाग, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। खाद्य विभाग द्वारा पात्र परिवारों को नवीन राशन कार्ड वितरित किए गए, जिससे उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त हो सकेगा। पंचायत विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों को उनके नए आवास की चाबियां सौंपी गई। अपने पक्के घर की चाबी पाकर हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान वय वंदन कार्ड प्रदान किए गए, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नोनी सुरक्षा योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बालिकाओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके भविष्य को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने का संदेश दिया गया 7 प्रधानमंत्री वय वंदन योजना अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक संबल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई।

मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, प्रोत्साहन राशि देकर बढ़ाया उत्साह-शिविर के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का भी विशेष सम्मान किया गया। कक्षा 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 10 मेधावी विद्यार्थियों को 10-10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार कक्षा 10वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 27 विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और शासन उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम कर जिले एवं प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने शासन द्वारा प्रतिभाओं को सम्मानित किए जाने की पहल की सराहना की।

जनता से सीधा संवाद, आवेदन देने के लिए किया प्रेरित-मंत्री दयाल दास बघेल ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों का जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीणों को अपनी समस्याएं एवं मांगें लिखित आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शासन का उद्देश्य प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना है, ताकि लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। शिविरों के माध्यम से मौके पर ही समस्याओं का सत्यापन एवं निराकरण किया जा रहा है तथा पात्र हितग्राहियों को तत्काल योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश-प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए मंत्री श्री बघेल ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि केवल कागजी कार्यवाही तक सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर त्वरित और प्रभावी कार्य सुनिश्चित करें।उन्होंने स्पष्ट कहा कि जन समस्याओं के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए आम जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें।

चिरायु योजना से बेमेतरा के सैकड़ों बच्चों को मिला नया जीवन

हृदय रोग से ग्रसित 6 गंभीर रोगियों का राज्य से बाहर नि:शुल्क इलाज

लक्ष्मी साहू, उम्र 14 वर्ष, ग्राम पेंड्रीतरई, जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित थी। बच्ची का सफल इलाज बालाजी हॉस्पिटल, रायपुर में करवाया गया।

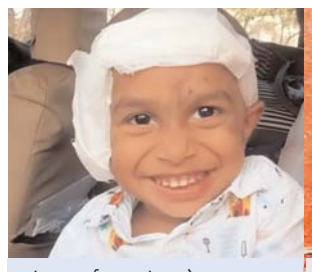

पांशुल शर्मा ग्राम संकरा बेरला जन्मजात बधिरता रोग का सफलताफुर्वक कॉकलियर इम्प्लांट एम्स हॉस्पिटल रायपुर

लूभांश वर्मा*, उम्र 4.5 माह, सुवरतला, जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित था। बच्चे का इलाज राज्य से बाहर करवाया गया

कंचन वर्मा पिता कमलेश वर्मा ग्राम - भैसा बेमेतरा जन्मजात बाधिरता चिरायु योजना के माध्यम से ऐम्स रायपुर कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी 23अप्रैल 2026 को करवाया गया

भास्कर यादव पिता अनिल यादव ग्राम करनजिया क्लबफुट सफ़लतापूर्वक ईलाज जिला अस्पताल पंडरी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

स्वास्थ्य विभाग जिला बेमेतरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ÷चिरायु÷ योजना के माध्यम से बेमेतरा जिले में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, बीमारियों की प्रारंभिक पहचान एवं निःशुल्क उपचार कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ अमृत लाल रोहलेडर के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री लता बंजारे के सक्रियता में सतत रूप से किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बेमेतरा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में ÷4ष्÷ अर्थात जन्मजात दोष (Defects at Birth), बीमारी (Diseases), पोषण संबंधी कमियों (Deficiencies) और विकासात्मक समस्याओं एवं विकलांगता (Developmental Delays & Disabilities) की समय पर पहचान कर समुचित उपचार एवं परामर्श उपलब्ध कराना है।जिले में 9 चिरायु दलों का संचालन सहायक जिला नोडल अधिकारी डॉ ऋषभ शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में बेमेतरा जिले में कुल 9 चिरायु दल प्रत्येक विकासखण्ड में दो एवं शहरी क्षेत्र में एक सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक दल में 1 पुरुष चिकित्सक, 1 महिला चिकित्सक, 1 फार्मासिस्ट तथा 1 ए.एन.एम. सम्मिलित हैं। इन प्रशिक्षित मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा प्रतिवर्ष जिले के 1300 शासकीय विद्यालयों के 1लाख 45 हजार विद्यार्थियों एवं 1200 आंगनबाड़ी केंद्रों के 61 हजार 311 बच्चों में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित कर बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है।

गंभीर रोगियों का राज्य से बाहर निःशुल्क इलाज-जटिल जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित कुल 06 बच्चों का इलाज राज्य शासन एवं राज्य नोडल एजेंसी के माध्यम से राशि स्वीकृत कराकर राज्य से बाहर के उच्च स्तरीय अस्पतालों में करवाया गया है। प्रमुख सफल प्रकरणः1. कमल वर्मा, उम्र 15 वर्ष, ग्राम मंजगांव, जटिल जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित था। बच्चे का इलाज अपोलो चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल, चेन्नई में करवाया गया, जिसके लिए दो चरणों में लगभग 8 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

2. लक्ष्मी साहू, उम्र 14 वर्ष, ग्राम पेंड्रीतरई, जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित थी। बच्ची का सफल इलाज बालाजी हॉस्पिटल, रायपुर में करवाया गया। 3. चिरायु योजना के माध्यम से जन्मजात बधिरता के 3 बच्चों कंचन वर्मा निवासी - भैंसा (बेमेतरा), रिहान सिंह निवासी - दोहतरा (नवागढ़) और पांशुल शर्मा निवासी - सांकरा (बेरला) का कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक एम्स रायपुर में करवाया गया। 4. युभांश वर्मा, उम्र 4.5 माह, सुवरतला, जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित था। बच्चे का इलाज राज्य से बाहर करवाया गया, जिसके लिए 6.5 लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत की गई।सीएमएचओ बेमेतरा ने जिलेवासियों से अपील की है कि यदि उनके आसपास 0 से 18 वर्ष तक का कोई बच्चा जन्मजात रोग या विकृति से ग्रसित है तो वे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या चिरायु दल से संपर्क कर निःशुल्क जांच एवं उपचार का लाभ लें।

दो वर्षों में 163 बच्चों को मिला लाभ-

चिरायु दलों द्वारा किए गए कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	बीमारी/ जन्मजात दोष	सत्र 2024-25	सत्र 2025-26
1	कटे-फटे होंठ एवं तालु	15	- 7
2	मुड़े हुए पैर		13 -
3			
3	जन्मजात मोतियाबिंद	4 -	6
4	जन्मजात बधिरता	7 -	4
5	जन्मजात हृदय रोग	60	- 43
6	न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट	-	1
	कुल	*99*	*64*

विधायक सुश्री लता उसेण्डी ने ग्राम बोलबोला में 8 लाख रुपये के निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन

कोण्डागांव/मूक पत्रिका

बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोण्डागांव विधायक सुश्री लता उसेण्डी ने गुरुवार को ग्राम बोलबोला में 8 लाख रुपये की लागत से होने वाले दो विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इन कार्यों में प्लाटपारा चौक के सामने 5 लाख रुपये की लागत से रंगमंच निर्माण तथा ग्राम पंचायत बोलबोला के जरेबेन्दरी में बुदर पोयाम के घर से प्रेम नेताम के घर तक 100 मीटर सीसी सड़क निर्माण कार्य, जिसकी लागत 3 लाख रुपये है, शामिल हैं। इस अवसर पर विधायक ने गांव के युवाओं को खेल सामग्री का भी वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सुश्री उसेण्डी ने कहा कि इन विकास कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गांव-गांव तक विकास कार्यों की सौगात पहुंचाई जा रही है। कार्यक्रम में जनपद उपाध्यक्ष टोमेन्द्र ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रामदई नाग, सरपंच श्रीमती पुष्पा पोयाम, उपसरपंच जयलाल पोयाम, धिनाराम कोर्राम, विरेन्द्र नेताम, चैतराम नेताम, गंगाराम पोयाम, श्रीमती गायत्री नेताम, श्रीमती राजिम पोयाम, श्रीमती मेहबती सेठिया, श्रीमती सुखदई पोयाम, श्रीमती कविता कोर्राम, श्रीमती मीना कोर्राम एवं श्रीमती गोमती कोर्राम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

बस्तर के 377 गाँवों में जन भागीदारी अभियान का शानदार आगाज

धरातल पर शिकायतों के निवारण और विकास की गति बढ़ाने पहल शुरू

जगदलपुर/मूक पत्रिका

बस्तर जिले के दूरस्थ अंचलों तक सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुँचाने और ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार जिला स्तर पर जन भागीदारी-सबसे दूर, सबसे पहले थीम के तहत आदि कर्मयोगी अभियान का औपचारिक प्रारंभ कर दिया गया है।

परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जगदलपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह विशेष अभियान धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत चयनित जिले के

377 ग्रामों में पूरी सक्रियता के साथ संचालित किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय स्तर के सूचना, शिक्षा, संचार कैम्पेन का मुख्य उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में सीधे जमीनी संपर्क स्थापित करना, शासन की सेवाओं की शत-प्रतिशत उपलब्धता सेवा संतृप्ति सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाना और आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान करना है।

अभियान के दौरान आयोजित होने वाली समस्त गतिविधियों का प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर उसे आदि प्रसारण पोर्टल पर भी अपलोड किया जा रहा है। इस सुनियोजित अभियान का शुभारंभ जिला, विकासखण्ड और चयनित सभी 377 ग्रामों में व्यापक उन्मुखीकरण ओरिएंटेशन कार्यक्रमों के साथ हुआ। कार्यक्रम के आगे बढ़ते ही, गाँवों में विकास को गति देने के लिए विशेष संतृप्ति शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण हेतु जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा जा रहा है। अभियान के अगले चरण में प्रशासनिक टीमों द्वारा विभिन्न ग्रामों का सघन भ्रमण किया गया, जहाँ अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर गाँवों की वास्तविक स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया और ग्रामीणों के बीच विभिन्न कल्याणकारी विषयों पर जागरूकता का प्रसार किया। ग्रामीणों को सीधे राहत पहुँचाने के उद्देश्य से अब अभियान के तहत विशेष जनसुनवाई कार्यक्रमों की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, जिनमें दैनिक आधार पर गतिविधियाँ संचालित कर लोगों की शिकायतों और उनके अधिकारों का त्वरित समाधान किया जा रहा है। इन जनसुनवाई सत्रों में सामने आने वाली सभी समस्याओं और उनके निराकरण की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देते हुए दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा।

इस बेहद महत्वपूर्ण और जन-उपयोगी पहल के शुरू होने पर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जगदलपुर के परियोजना प्रशासक ने जिले के ग्रामीणों से अनुरोध किया है कि सभी ग्रामीणजन इस अभियान में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों, अपनी समस्याओं को दर्ज कराएं और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित होकर इस महा-अभियान को सफल बनाएं।

पेट्रोल-डीजल की किल्लत से मचा हाहाकार... जनता त्रस्त पंप मालिक मस्त

खरसिया/मूक पत्रिका

वर्तमान में तेजी से बढ़ रही महंगाई के दौर में जनता पहले ही गैस सिलेंडर के संकट से निकल नही पाई है की अब इस भीषण गर्मी में पेट्रोल-डीजल के लिए पंपों में भटकना एवं घंटो लंबी कतारे पर लगने के बावजूद पंपों में ऑयल नही मिलना जनता की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। खरसिया शहर में पेट्रोल पंपों में स्टॉक होने के बावजूद जानबूझकर कृत्रिम अभाव की स्थिति बनाई जा रही है। जानकारी यह भी मिल रही है की पंप ड्राई है कहकर बाहर की गाड़ियों को बड़ी मात्रा में मिलावटी पेट्रोल-डीजल एक्स्ट्रा मुनाफा लेकर दिया जा रहा है। ऐसी संकट की घड़ी में पंप मालिको द्वारा कृत्रिम स्थिति बनाकर कालाबाजारी किया जाना उचित नहीं है। शासन प्रशासन को चाहिए की ऐसे पंपों की जांच कर अनियमितता पाए जाने पर पंप को सील करने की कार्यवाही करें।

जन समस्या निवारण शिविर में होंगे शामिल, 18.65 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण एवं भूमिपूजन

- उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज बेमेतरा प्रवास पर रहेंगे

बेमेतरा/मूक पत्रिका

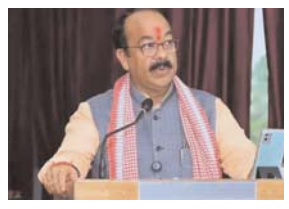

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव आज जिला बेमेतरा के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत वे विकासखंड बेरला के ग्राम पंचायत आनंदगांव में आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में शामिल होंगे तथा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे। प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार उपमुख्यमंत्री अरुण साव सुबह 11:30 बजे रायपुर स्थित निवास से प्रस्थान करेंगे और दोपहर 12:30 बजे ग्राम पंचायत आनंदगांव पहुंचेंगे। यहां वे आमजन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं एवं मांगों से अवगत होंगे तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश देंगे। कार्यक्रम के दौरान शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी हितग्राहियों को दी जाएगी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री साव द्वारा गोआरा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल 18 करोड़ 65 लाख 07 हजार रुपये की लागत से तैयार एवं प्रस्तावित 12 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया जाएगा। इन कार्यों में ग्रामीण विकास, पेयजल व्यवस्था तथा पंचायत स्तर के अधोसंरचना विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्माण कार्य शामिल हैं। जानकारी के अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिला बेमेतरा द्वारा 46.22 लाख रुपये की लागत से 3 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया जाएगा। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला बेमेतरा के अंतर्गत 12 करोड़ 87 लाख 80 हजार रुपये की लागत से निर्मित 1 कार्य का लोकार्पण किया जाएगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत बेरला के अंतर्गत 4 करोड़ 53 लाख 54 हजार रुपये की लागत से 4 कार्यों का भूमिपूजन तथा 77.51 लाख रुपये की लागत से 4 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इस प्रकार जनपद पंचायत बेरला के माध्यम से कुल 8 विकास कार्यों को जनता को समर्पित किया जाएगा, जिनकी कुल लागत 5 करोड़ 31 लाख 05 हजार रुपये है। सभी विभागों को मिलाकर कुल 7 कार्यों का भूमिपूजन एवं 5 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इन विकास कार्यों की कुल लागत 18 करोड़ 65 लाख 07 हजार रुपये है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्र में पेयजल, आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास से संबंधित सुविधाओं का विस्तार होगा तथा आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। कार्यक्रम पश्चात उपमुख्यमंत्री अरुण साव दोपहर 1:30 बजे आनंदगांव से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

अंदरूनी गांवों तक पहुंचे विधायक विक्रम मंडावी, ग्रामीणों से जाना हाल

चार दिन में 33 गांवों का दौरा, स्कूल, सड़क, अस्पताल और रोजगार की उठी मांग

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। विधायक विक्रम मंडावी ने चार दिनों तक बीजापुर और उसूर विकासखंड के 33 अंदरूनी गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे ग्रामीणों ने विधायक के सामने स्कूल, अस्पताल, सड़क, शुद्ध पेयजल, बिजली, आंगनबाड़ी केंद्र और रोजगार की मांग रखी।दौरे के दौरान विधायक मंडावी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए भरोसा दिलाया कि सभी मांगों को सरकार तक पहुंचाकर समाधान के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उसूर और गंगालूर क्षेत्र के कई गांव अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और सरकार तक ग्रामीणों की आवाज पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है।विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे, ताकि युवाओं को गांव में ही काम मिल सके। दौरे के दौरान कई गांवों में ग्रामीणों ने सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को प्रमुख समस्या बताया।विधायक विक्रम मंडावी ने गंगालूर और उसूर क्षेत्र के पेदाकोरमा, पालनार, सावनार, तोड़का, ईतवार, कोरचोली, पुसानार, कावड़गांव, हिरमगुण्डा, मुदवेंडी, पीड़िया, डोडीतुमनार, गमपुर, पेदागेलूर, गोमगुड़ा, पालागुड़ा, कंचाल, गण्डाराजगुड़ा, एर्रापल्ली, मेटागुड़ा, मंगलतोंग, रासपल्ली, यमपुर, सापेड़, बड़े तर्रेम, पोलमपल्ली, कोंजेर, नरसापुर, टेकुलगुड़ा, मुरकीपाड़, गुण्डाम कोत्तागुड़ा, पुसबाका और चिपुरभट्टी सहित कई गांवों का दौरा किया। दौरे में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर, उसूर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य मनोज अवलम, सुनील उद्दे, ब्लॉक अध्यक्ष मंगल राना, जनपद अध्यक्ष सोनू पोटाम, उपाध्यक्ष दिनेश पुजारी, भीमा कट्टम, पुरुषोत्तम खत्री, जनपद सदस्य अनीता तेलम, सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पहली बार इतने अंदरूनी गांवों तक पहुंचा कोई विधायक - ग्रामीणों के मुताबिक यह पहला मौका है जब कोई विधायक जिले के इतने दूरस्थ और अंदरूनी गांवों तक पहुंचा। कई गांवों में ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग लंबित है। विधायक के दौरे से ग्रामीणों में उम्मीद जगी है कि अब उनकी समस्याओं पर गंभीरता से काम होगा।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जल्द शुरू होगी सीएम हेल्पलाइन

शीघ्र होगा प्रारंभ टोल फ्री नंबर 1076 पर नि:शुल्क दर्ज करा सकते है शिकायत

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप प्रदेश के नागरिकों को शासकीय सेवाओं एवं योजनाओं तक सरल पहुंच और उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा सीएम हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ की जा रही है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के अंतर्गत संचालित इस प्रणाली का उद्देश्य नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने, शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने तथा समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत, सुलभ और विश्वसनीय माध्यम उपलब्ध कराना है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे की उपस्थिति में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण सभी अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए और शिकायतों के समाधान में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। बैठक में सुशासन एवं अभिसरण विभाग से अनुराग दीवान, अंशुल, चंदन, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे, संयुक्त कलेक्टर संदीप ठाकुर तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही विकासखंड स्तर के सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मध्यम से वर्चुअली शामिल हुए।राज्य स्तर से गठित अधिकारियों के प्रशिक्षण दल के प्रमुख एवं सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सलाहकार श्री दीवान ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रदेश का कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 सहित वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप जैसे आधुनिक मल्टी चौनल किसी भी माध्यम से कॉल करके, 24म7 अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज होते ही उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत की पूरी स्थिति किस विभाग में, किस अधिकारी के पास लंबित है, और कार्यवाही हुई या नहीं. इसके साथ ही समाधान में कितना समय लगेगा इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी।

शिकायत दर्ज होने के बाद उसे संबंधित विभाग और अधिकारी तक तुरंत पहुंचाया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया तकनीक आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम से जुडी होगी, जिसमें हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और शिकायतों के अनावश्यक लंबित रहने की संभावना नही होगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों का फीडबैक इस पूरी प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत है। समाधान होने के बाद संबंधित नागरिक से सीधे संपर्क कर उसकी प्रतिक्रिया ली जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि समस्या का वास्तव में समाधान हुआ है या नहीं। व्यक्ति अगर समाधान से संतुष्ट होता है, तभी शिकायत का पूर्ण निराकरण माना जाएगा। लेकिन यदि काई असंतुष्ट है तो शिकायत स्वतः सक्रिय हो जाएगी। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग की इस व्यवस्था से प्रशासन अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और सक्रिय बनेगा। जिससे आम नागरिकों की समस्याओं का तेजी से निराकरण सुनिश्चित होगा।

सीएम हेल्पलाइन सेंटर सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे संचालित रहेगा। नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 पर कॉल कर, ऑनलाइन पोर्टल, व्हाट्सऐप या लिखित आवेदन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे तथा उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रणाली राज्य में पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन को मजबूत करने और आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार कार्य कर रही है।

संपादकीय

तकनीक की तरक्की और ठगी का जाल

हैरानी की बात यह है कि डिजिटल संसार की अवांछित गतिविधियों पर बारीक निगरानी रखने का दावा करने वाली पुलिस कई बार समय पर अपराधियों को नहीं पकड़ पाती।इसमें कोई दोराय नहीं कि आधुनिक तकनीक की दुनिया में डिजिटल सेवाओं ने मनुष्य के जीवन को आसान बनाया है और आज कई तरह की सुविधाएं आम लोगों की पहुंच में हैं। उम्मीद यह भी की गई थी कि जैसे-जैसे सामान्य कामकाज में डिजिटल संसार का दखल बढ़ेगा, वैसे-वैसे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार पर काबू पाना आसान होगा। काफी हद तक ऐसा हुआ भी है।मगर इसके समांतर इसी डिजिटल तंत्र के दायरे में अपराध के नए स्वरूप विकसित हुए और आज यह भारत सहित दुनिया भर में एक नई चुनौती बनते जा रहे हैं।पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने शुक्रवार को अब तक के सबसे बड़े साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया, जिसमें काल सेंटर के नाम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। फर्जी कंपनी चलाने वाले और ठगी में शामिल एक सौ बत्तीस लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।खबरों के मुताबिक, इस गिरोह में शामिल लोग दूर बैठे कंप्यूटर तक पहुंच हासिल करते थे या फर्जी वायरस और सुरक्षा चेतावनी के जरिए विदेशी नागरिकों को निशाना बनाते थे। लोगों को ई-मेल और बैंक खाते में सेंध लगने का डर दिखा कर उनसे भारी राशि की ठगी की जाती थी।जाहिर है, डिजिटल दुनिया में जिन आधुनिक तकनीकों को लोगों के जीवन को आसान बनाने और उनकी आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित बनाने के लिए ज्यादा बेहतर बताया जाता है, उसी में अब अपराध का ऐसा संजाल खड़ा हो चुका है, जिसमें हर रोज बड़ी संख्या में लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं।पिछले कुछ समय से खासतौर पर 'डिजिटल अरेस्ट' के मामलों में खासी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें दूर बैठे अपराधी सिर्फ स्मार्टफोन पर वीडियो काल के जरिए किसी व्यक्ति को एक तरह से बंधक बना लेते हैं और डरा-धमका कर भारी रकम वसूल लेते हैं।हैरानी की बात यह है कि डिजिटल संसार की अवांछित गतिविधियों पर बारीक निगरानी रखने का दावा करने वाली पुलिस कई बार समय पर अपराधियों को नहीं पकड़ पाती। सच यह है कि इस क्षेत्र में अपराध का दायरा जितना विस्तृत और जटिल होता जा रहा है, उसके मुकाबले सुरक्षा या बचाव के साथ-साथ अपराध पर काबू पाने के इंतजाम नाकाफी हैं।

'आर्थिक स्वराज' की सिद्धि का राष्ट्र मंत्र

भारत आज विश्व की सबसे तीव्र गति से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित है। उद्योगों का विस्तार, बढ़ती जनसंख्या, परिवहन की आवश्यकता और ऊर्जा की निरंतर बढ़ती मांग ने पेट्रोलियम पर हमारी निर्भरता को अत्यधिक बढ़ा दिया है। स्थिति यह है कि भारत अपनी कुल आवश्यकता का लगभग 80 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसका अर्थ यह है कि देश की ऊर्जा व्यवस्था का बहुत बड़ा भाग विदेशी बाजारों, वैश्विक संघर्षों और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों की अस्थिरता पर निर्भर है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका सीधा प्रभाव भारतीय अर्थतंत्र पर पड़ता है। पेट्रोल-डीजल महंगे होते हैं, परिवहन लागत बढ़ती है, उद्योगों का व्यय बढ़ता है और अंततः महंगाई आम नागरिक तक पहुंचती है। एक प्रकार से तेल केवल ईंधन नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की धमनियों में बहने वाला रक्त है। यदि यह रक्त अत्यधिक महंगे आयात पर निर्भर रहेगा, तो आर्थिक शरीर पर दबाव स्वाभाविक है।

(प्रणय विक्रम सिंह)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोलियम और स्वर्ण की खपत को संयमित करने का आह्वान केवल एक आर्थिक सलाह नहीं है, बल्कि यह भारत की दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक वित्तीय स्थिरता से जुड़ा हुआ दूरदर्शी राष्ट्रीय चिंतन है।

पहली दृष्टि में यह विषय सामान्य प्रतीत हो सकता है, किंतु इसकी गहराई में उतरने पर स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक दबाव डालने वाले दो प्रमुख आयात कच्चा तेल और स्वर्ण ही हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री का यह संदेश मात्र बचत का आग्रह नहीं, बल्कि आर्थिक स्वराज की सिद्धि का राष्ट्रमंत्र है।

भारत आज विश्व की सबसे तीव्र गति से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित है। उद्योगों का विस्तार, बढ़ती जनसंख्या, परिवहन की आवश्यकता और ऊर्जा की निरंतर बढ़ती मांग ने पेट्रोलियम पर हमारी निर्भरता को अत्यधिक बढ़ा दिया है। स्थिति यह है कि भारत अपनी कुल आवश्यकता का लगभग 80 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसका अर्थ यह है कि देश की ऊर्जा व्यवस्था का बहुत बड़ा भाग विदेशी बाजारों, वैश्विक संघर्षों और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों की अस्थिरता पर निर्भर है।

जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका सीधा प्रभाव भारतीय अर्थतंत्र पर पड़ता है। पेट्रोल-डीजल महंगे होते हैं, परिवहन लागत बढ़ती है, उद्योगों का व्यय बढ़ता है और अंततः महंगाई आम नागरिक तक पहुंचती है। एक प्रकार से तेल केवल ईंधन नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की धमनियों में बहने वाला रक्त है। यदि यह रक्त अत्यधिक महंगे आयात पर निर्भर रहेगा, तो आर्थिक शरीर पर दबाव स्वाभाविक है।

इसी प्रकार स्वर्ण के प्रति भारतीय समाज का भावनात्मक और सांस्कृतिक आकर्षण भी हमारी वित्तीय संरचना को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता है और अपनी आवश्यकता का लगभग पूरा सोना विदेशों से आयात करता है। विवाह, परंपराएं, निवेश और सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सभी कारणों से भारत में सोने की मांग लगातार बनी रहती है। लेकिन इसका आर्थिक पक्ष अत्यंत गंभीर है।

जब भारत भारी मात्रा में सोना खरीदता है, तो उसके बदले विदेशी मुद्रा विशेषकर अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। यही स्थिति तेल के साथ भी है। परिणामस्वरूप देश का बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार निरंतर बाहर जाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह होता है। यही भंडार संकट के समय आयात, अंतरराष्ट्रीय भुगतान और वित्तीय स्थिरता को संभालता है। यदि यह भंडार अत्यधिक दबाव में आए, तो रुपए की कीमत कमजोर होने लगती है, आयात महंगे हो जाते हैं और वैश्विक बाजार में देश की आर्थिक साख प्रभावित होती है।

यही कारण है कि प्रधानमंत्री का यह आह्वान सिर्फ 'कम खर्च' का संदेश नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक अनुशासन का अभियान है। यदि भारत पेट्रोलियम की खपत और स्वर्ण के प्रति अंधाधुंध निवेश प्रवृत्ति को नियंत्रित कर सके, तो आयात बिल में भारी कमी लाई जा सकती है। आयात बिल में होने वाली इस अरबों डॉलर की बचत का उपयोग देश के आंतरिक विकास, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक सैन्य सशक्तिकरण, उन्नत शिक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं में किया जा सकेगा।

महाभारत में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध का ही नहीं, बल्कि 'संयमित कर्म' का भी उपदेश दिया था। भारतीय चिंतन में संसाधनों का अनियंत्रित उपभोग कभी आदर्श नहीं माना गया। यही कारण है कि हमारी सभ्यता ने 'यज्ञ' की अवधारणा दी, जहां व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि व्यापक लोककल्याण के लिए त्याग और अनुशासन अपनाता है। पेट्रोलियम, स्वर्ण और विदेशी मुद्रा संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान भी उसी 'राष्ट्रयज्ञ' का आधुनिक स्वरूप है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की सजग भागीदारी आवश्यक है।

भारतीय समाज में सोने को एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से तिजोरियों और लॉकरों में बंद यह सोना एक 'डेड इन्वेस्टमेंट' (निष्क्रिय निवेश) है, जो देश के आर्थिक चक्र में कोई योगदान नहीं देता। यहीं भारतीय निवेश प्रवृत्ति पर पुनर्विचार की आवश्यकता सामने आती है। यदि देश का नागरिक सोने के भौतिक उपभोग को कम करे या इसके विकल्प के रूप में सरकार के 'सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड' जैसे डिजिटल साधनों को अपनाए, तो वह पैसा देश के बैंकिंग सिस्टम और विकास कार्यों में लगा रहेगा। यह दृष्टि भारत को निष्क्रिय संचय से उत्पादक निवेश की दिशा में ले जाने का प्रयास है।

'देखो अपना देश' और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का आग्रह भी इसी व्यापक आर्थिक दृष्टि का हिस्सा है। हर वर्ष करोड़ों भारतीय विदेश यात्राओं पर विशाल मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं। यदि उसी खर्च का एक बड़ा भाग भारत के पर्यटन स्थलों काशी, अयोध्या, केदारनाथ, लक्षद्वीप, अंडमान, पूर्वोत्तर, राजस्थान, कच्छ, केरला या हिमालयी क्षेत्रों पर हो, तो उसका सीधा लाभ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा।

घरेलू पर्यटन महज यात्रा नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था का जीवन-तंत्र है। इससे होटल उद्योग, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार, रेस्तरां, गाइड, टैक्सी चालक और छोटे व्यापारी सभी सशक्त होते हैं। एक पर्यटक केवल पैसा खर्च नहीं करता, वह स्थानीय रोजगार को गति देता है। इस दृष्टि से यह आह्वान 'देश का पैसा देश में' रखने का आर्थिक मंत्र भी है।

भारत के इतिहास में ऐसे राष्ट्रीय आह्वानों की एक गौरवपूर्ण परंपरा रही है। जब-जब देश चुनौतियों से घिरा, तब-तब नेतृत्व ने केवल शासनादेश नहीं दिए, बल्कि जनचेतना को जगाने का प्रयास किया। लाल बहादुर शास्त्री का वह ऐतिहासिक आह्वान आज भी स्मरणीय है, जब देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था और उन्होंने राष्ट्रहित में सप्ताह में एक दिन उपवास रखने का आग्रह किया था। वह केवल भोजन बचाने की अपील नहीं थी, वह आत्मसंयम, अनुशासन और राष्ट्र के लिए व्यक्तिगत सुविधा का त्याग करने की भारतीय परंपरा का जागरण था। देशवासियों ने भी उसे आदेश नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व के रूप में स्वीकार किया। घरों में चूल्हे कम जले, होटलों ने भोजन परोसना बंद किया और समाज ने यह सिद्ध किया कि भारत केवल सरकारों से नहीं, बल्कि जनभागीदारी से चलता है।

इसी प्रकार समय-समय पर देश के नेतृत्व ने स्वदेशी, बचत, आत्मनिर्भरता और उत्पादन बढ़ाने जैसे आह्वानों के माध्यम से जनता को राष्ट्रनिर्माण में सहभागी बनाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश उसी राष्ट्रीय परंपरा का आधुनिक विस्तार है। अंतर केवल परिस्थितियों का है, तब चुनौती खाद्यान्न की थी, आज चुनौती ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी मुद्रा संरक्षण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की है। किंतु दोनों के मूल में 'राष्ट्र प्रथम' का ही भाव है।

भारतीय राष्ट्रचिंतन में आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता की यह परंपरा केवल राजनीतिक नीतियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसे सभ्यतागत दृष्टि के रूप में देखा गया।

महात्मा गांधी ने स्वराज को केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के रूप में नहीं देखा था। उनके चिंतन में स्वराज, ग्राम स्वराज और आर्थिक स्वराज एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। उनका मानना था कि जब गांव आत्मनिर्भर होंगे, स्थानीय उत्पादन सशक्त होगा, संसाधनों का संयमित उपयोग होगा और राष्ट्र आर्थिक रूप से बाहरी निर्भरता से मुक्त होगा, तभी वास्तविक स्वराज की स्थापना संभव होगी।

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत, 'वोकल फॉर लोकल', स्थानीय पर्यटन, ऊर्जा संरक्षण और स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से उसी आर्थिक स्वराज की आधुनिक अवधारणा को मूर्त रूप दे रहे हैं। वे केवल नीतियों के निर्माता नहीं, बल्कि आधुनिक भारत में आर्थिक स्वराज के शिल्पकार हैं। वास्तव में पूर्ण स्वराज का रास्ता आर्थिक स्वराज और ग्राम स्वराज से होकर ही निकलता है।

इसके अतिरिक्त यह पहल भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता से भी जुड़ी हुई है। ऊर्जा और विदेशी मुद्रा पर अत्यधिक बाहरी निर्भरता किसी भी राष्ट्र को वैश्विक दबावों के प्रति संवेदनशील बना देती है। यदि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, युद्ध, प्रतिबंध या आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं, तो तेल और डॉलर पर निर्भर राष्ट्रों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता और विदेशी मुद्रा संरक्षण केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है।

प्रधानमंत्री की यह सोच उसी व्यापक 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टि का हिस्सा है, जिसमें भारत केवल उपभोक्ता राष्ट्र नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर वैश्विक शक्ति बनकर उभरे। यह आह्वान भारतीयों को यह समझाने का प्रयास भी है कि राष्ट्रनिर्माण केवल सरकारों से नहीं होता, नागरिकों की जीवनशैली, उपभोग की आदतें और आर्थिक अनुशासन भी उसमें समान रूप से भागीदार होते हैं। यदि देश का नागरिक अनावश्यक ईंधन की खपत कम करे, स्थानीय उत्पादों को अपनाए, विवेकपूर्ण निवेश करे और भारत के भीतर पर्यटन को बढ़ावा दे, तो यह केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रहित का सक्रिय योगदान बन जाएगा।

वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश अर्थव्यवस्था के माध्यम से राष्ट्रशक्ति को सुदृढ़ करने का आह्वान है। यह भारत को भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों, वैश्विक आर्थिक अस्थिरताओं और विदेशी निर्भरता से मुक्त कर एक मजबूत, आत्मनिर्भर और स्थायी आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में उठाया गया दूरदर्शी कदम है।ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं

'अच्छे दिन' से 'संकट की घड़ी' तक? अब जनता से संयम की अपेक्षा

(तवलीन सिंह)

भारत में अंग्रेज जब राज करते थे, तो उन्होंने भी अपने लिए बनाए थे बड़े-बड़े घर, ताकि उनकी शान हम गुलामों में बढ़ जाए। इन मकानों में 1947 में रहने लगे हमारे जन प्रतिनिधि और अब ऐसी आदत पड़ी हुई है शान से रहने की कि कोई बहुत ही साहसी प्रधानमंत्री होगा जो इस आदत को छोड़ सकेगा।

काश चुनावों का मौसम थोड़ा और लंबा होता। उसके खत्म होते ही प्रधानमंत्री ने चेताया हमको कि अच्छे दिन अभी रूई की बत्ती की तरह उड़ गए हैं और बुरे दिनों की तैयारी हम सबको करनी होगी। एक साल तक रहेंगे मायूसी और तंगी भरे ये दिन, जिनमें न हम किसी खुशी के मौके पर सोना खरीद सकेंगे, न विदेश यात्राएं कर सकेंगे, न कोई दूसरे तरीके से विदेशी मुद्रा इस्तेमाल कर सकेंगे। ऊपर से आग्रह यह भी किया प्रधानमंत्री ने कि जहां तक हो सके, हम घर से काम करने का प्रयास करें और अगर बाहर जाना ही है कहीं, तो निजी गाड़ियों के बदले बस, टैक्सी या मेट्रो से जाएं। निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करना ही है, तो 'कारपूलिंग' करें। यह सुझाव हैं मध्यवर्ग लोगों के लिए। गरीब किसानों के लिए सुझाव यह था प्रधानमंत्री का कि कीमती खाद, जिसका आयात विदेशों से होता है, उसको त्याग कर खेती पुराने तरीकों से करना शुरू करें। जिस तरह विदेश से आयात की हुई महंगी रासायनिक खाद के आने से पहले होती थी। प्रधानमंत्री शायद भूल गए यह सुझाव देते हुए कि वह ऐसा दौर था, जब भारतीय किसानों का उत्पाद इतना थोड़ा था कि हमको विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ता था। मेरी उमर के लोग भूले नहीं हैं वह दौर जब समंदर के रास्ते आता था गेहूं और धान।

प्रधानमंत्री शायद यह भी भूल गए थे कि श्रीलंका में जब राजपक्षे बंधु राज करते थे, तो उन्होंने भी अपने किसानों को यही सुझाव दिया था और परिणाम यह हुआ कि अनाज के दाम इतने बढ़ गए थे कि क्रांति पर उतर आए थे श्रीलंका के लोग। याद कीजिए वे नजारे, जिनमें आम लोगों ने राष्ट्रपति के महल में घुस कर तोड़फोड़ और लूटपाट की थी। यह वर्ष 2022 की बात है सो शायद आपको भी याद होगा कि राष्ट्रपति राजपक्षे को देश छोड़ कर भागना पड़ा था। विनम्रता से प्रधानमंत्री से आग्रह करती हूं कि यह वाला सुझाव वापस ले लें।

सुझाव मेरी तरफ से और भी हैं, बिल्कुल वैसे जैसे प्रधानमंत्री ने अपने काफिले की गाड़ियां कम करने का फैसला किया है। उनको अब अपने मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को भी आदेश देना चाहिए कि पेट्रोल-डीजल की किल्लत इतनी है अब कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने काफिले को बंद कर एक ही गाड़ी में अपने सुरक्षा कर्मियों को बिठा कर सफर करें। भारत में बड़े काफिलों की आदत डाल रखी है हमारे राजनेताओं ने, लेकिन ऐसा विकसित पश्चिमी देशों में नहीं होता है। अक्सर वहां के राजनेता जब अपने घर से दफ्तर जाते हैं, तो उनकी एक गाड़ी होती है, दस नहीं। कई देशों में तो प्रधानमंत्री मेट्रो से जाते हैं। संकट की घड़ी में नेतृत्व की सख्त जरूरत होती है, तो प्रधानमंत्री आप दिखाइए कि सरकारी खर्चा आप कितना कम कर सकते हैं।

मैंने पहले भी कहा है बहुत बार कि विकसित लोकतांत्रिक देशों में जन प्रतिनिधियों को सरकारी कोठियां नहीं मिलती हैं। अपनी तनख्वाह से ढूंढ़ते हैं अपने लिए किराए के आवास। अपनी तनख्वाह से खर्च करते हैं पैसे गैस, फोन, पानी और बिजली पर। ऐसा हमारे देश में इसलिए नहीं हुआ है, क्योंकि नेहरूजी बहुत प्रभावित थे सोवियत संघ से, सो उसकी नकल करने का फैसला किया उन्होंने। रूस और चीन जैसे तानाशाह कम्युनिस्ट देशों में होता यह है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहते हैं असली महलों में, जहां पहले रहते थे बादशाह और राजा। जबकि जनता को रहना पड़ता है झुग्गी बस्तियों में।

जब लोकतंत्र नहीं होता है, तो सवाल करने वाले भी नहीं होते हैं। भारत में अंग्रेज जब राज करते थे, तो उन्होंने भी अपने लिए बनाए थे बड़े-बड़े घर, ताकि उनकी शान हम गुलामों में बढ़ जाए। इन मकानों में 1947 में रहने लगे हमारे जन प्रतिनिधि और अब ऐसी आदत पड़ी हुई है शान से रहने की कि कोई बहुत ही साहसी प्रधानमंत्री होगा जो इस आदत को छोड़ सकेगा। आप कर सकते हैं क्या?

संकट की घड़ी में साहस दिखाने की जरूरत है। संकट अभी शुरू ही हुआ है। आगे-आगे देखते रहिए होगा क्या। डोनाल्ड ट्रंप चीन गए शी जिनपिंग से मिलने, लेकिन जाने से पहले उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान युद्ध के बारे में वे बात नहीं करना चाहते हैं शी से बावजूद इसके कि इस युद्ध को रोक सकता है कोई तो सिर्फ चीन। सो युद्ध लंबा चलने वाला है। इसका सबसे अधिक नुकसान होने वाला है भारत जैसे देशों में जो पूरी तरह तेल के लिए निर्भर हैं विदेश से आयात पर। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर मंदी छाने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन इस मंदी का असली नुकसान हमको देखना पड़ेगा अपने देश में।

प्रधानमंत्री मोदी खुद निकले हुए हैं विदेशी दौरे पर जिसकी योजना शायद बहुत पहले बनाई गई थी, लेकिन वे जानते हैं अच्छी तरह कि उनके मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं अमेरिका और यूरोप में और गर्मियों के मौसम में मंत्रियों की एक पूरी टोली निकल पड़ती है इन देशों की तरफ। जाते हैं सरकारी काम का बहाना करके, लेकिन असली मकसद है अपने बच्चों से मिलना और उनके साथ सैर-सपाटा करना। अनुमान लगाया जाता है कि मोदी के मंत्रिमंडल में कोई बीस मंत्री ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। अपनी तरफ से यह कहना चाहती हूं कि मेरी जानकारी में शायद एक भी बड़ा राजनेता या आला अधिकारी नहीं है, जिनके बच्चे किसी महंगे विदेशी कालेज में दाखिल न हुए हों। इनके पास पैसे कहां से आते हैं अपने बच्चों को इतनी महंगी शिक्षा दिलाने के लिए, मैं नहीं जानती।

चीन-अमेरिका की निकटता से भारत के सामने वैश्विक चुनौतियाँ

दुनिया एक बार फिर ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहाँ दो महाशक्तियों-अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते संवाद, आपसी मुलाकातों और कूटनीतिक समीकरणों को केवल द्विपक्षीय संबंधों के रूप में नहीं देखा जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संवाद और संभावित समझौतों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाओं का दौर चल रहा है। एक वर्ग इसे विश्व अर्थव्यवस्था के लिए राहतकारी कदम मान रहा है, क्योंकि इससे बढ़ती महंगाई, व्यापारिक अवरोधों और युद्धजन्य संकटों में कमी आने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि यह निकटता भविष्य में एक ऐसे विश्व संरचना को जन्म दे सकती है जहाँ दुनिया की दिशा पुनः कुछ महाशक्तियों के हाथों में सिमट जाए और विकासशील तथा अर्धविकसित देशों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी हो जाएँ।

(ललित गर्ग)

आज अमेरिका और चीन मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 44 प्रतिशत हिस्से को प्रभावित करते हैं। विश्व व्यापार, तकनीकी विकास, ऊर्जा बाजार, वैश्विक निवेश, वित्तीय संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक निर्णयों पर इन दोनों देशों का गहरा प्रभाव है। ऐसे में इनके संबंधों में किसी भी प्रकार का बदलाव पूरी दुनिया की दिशा बदलने की क्षमता रखता है।

दुनिया एक बार फिर ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहाँ दो महाशक्तियों-अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते संवाद, आपसी मुलाकातों और कूटनीतिक समीकरणों को केवल द्विपक्षीय संबंधों के रूप में नहीं देखा जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संवाद और संभावित समझौतों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाओं का दौर चल रहा है। एक वर्ग इसे विश्व अर्थव्यवस्था के लिए राहतकारी कदम मान रहा है, क्योंकि इससे बढ़ती महंगाई, व्यापारिक अवरोधों और युद्धजन्य संकटों में कमी आने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि यह निकटता भविष्य में एक ऐसे विश्व संरचना को जन्म दे सकती है जहाँ दुनिया की दिशा पुनः कुछ महाशक्तियों के हाथों में सिमट जाए और विकासशील तथा अर्धविकसित देशों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी हो जाएँ। भारत जैसे देशों के लिए यह परिस्थिति अवसर और चुनौती दोनों लेकर आई है।

आज अमेरिका और चीन मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 44 प्रतिशत हिस्से को प्रभावित करते हैं। विश्व व्यापार, तकनीकी विकास, ऊर्जा बाजार, वैश्विक निवेश, वित्तीय संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक निर्णयों पर इन दोनों देशों का गहरा प्रभाव है। ऐसे में इनके संबंधों में किसी भी प्रकार का बदलाव पूरी दुनिया की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध, टैरिफ विवाद, तकनीकी प्रतिबंध और ताइवान से जुड़े तनावों ने विश्व अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाला। कोरोना महामारी के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ टूट गईं, रूस-यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा संकट बढ़ाया और पश्चिम एशिया के संघर्षों ने दुनिया को अस्थिरता की ओर धकेला। इन परिस्थितियों में यदि अमेरिका और चीन संवाद और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बल मिल सकता है।

विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होने से सबसे पहले वैश्विक बाजारों को राहत मिलेगी। निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, तकनीक तथा विनिर्माण क्षेत्रों में लागत घट सकती है। इससे महंगाई पर भी नियंत्रण संभव है। किंतु यह केवल तस्वीर का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि यदि दोनों महाशक्तियाँ वैश्विक व्यापारिक नियमों और आर्थिक नीतियों को अपने हितों के अनुसार तय करने लगें तो छोटे देशों की आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। दुनिया पहले भी उपनिवेशवाद और आर्थिक नियंत्रण की राजनीति देख चुकी है, अब आशंका यह है कि कहीं आर्थिक वैश्वीकरण का नया स्वरूप महाशक्तियों के संयुक्त वर्चस्व में परिवर्तित न हो जाए। इसी संदर्भ में जी-2 यानी अमेरिका और चीन केंद्रित विश्व व्यवस्था की चर्चा तेज हुई है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विश्व धीरे-धीरे बहुध्रुवीय व्यवस्था से हटकर दो महाशक्तियों के प्रभाव वाले ढाँचे की ओर बढ़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो वैश्विक नीतियों, व्यापारिक समझौतों और सुरक्षा संबंधी निर्णयों में छोटे देशों की भूमिका सीमित हो सकती है। यह स्थिति भारत जैसे देशों के लिए विशेष चिंता का विषय है क्योंकि भारत हमेशा से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और सामूहिक वैश्विक नेतृत्व का समर्थक रहा है।

भारत की स्थिति यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत न तो पूरी तरह अमेरिकी खेमे में है और न ही चीन के प्रभाव क्षेत्र में। भारत ने लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाई है। अमेरिका के साथ भारत के रक्षा, तकनीकी और आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। क्वाड जैसे मंचों में भारत की सक्रिय भूमिका है। दूसरी ओर चीन भारत का पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच सीमा विवादों के बावजूद व्यापारिक संबंध व्यापक हैं। यही कारण है कि अमेरिका और चीन की बढ़ती निकटता भारत के लिए केवल बाहरी घटना नहीं बल्कि रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन का विषय है। भारत और चीन की तुलना करें तो चीन ने पिछले तीन दशकों में विनिर्माण, निर्यात, आधारभूत संरचना और तकनीकी उत्पादन के माध्यम से स्वयं को वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित किया। चीन की आर्थिक नीति केंद्रीकृत और तीव्र निर्णय क्षमता वाली रही है। इसके विपरीत भारत का विकास लोकतांत्रिक व्यवस्था, विविधता और संस्थागत संतुलन पर आधारित रहा है। भारत की शक्ति उसकी युवा आबादी, लोकतंत्र, सेवा क्षेत्र और डिजिटल क्षमता में निहित है, जबकि चीन की शक्ति विनिर्माण, निर्यात और पूंजी निवेश में रही है। अमेरिका के साथ चीन के संबंधों में सुधार होने की स्थिति में भारत के सामने यह चुनौती होगी कि वह अपनी आर्थिक और रणनीतिक उपयोगिता को और अधिक प्रभावशाली बनाए।

भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर चाइना प्लस वन रणनीति में निहित है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पिछले वर्षों में चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रयास किए हैं। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ चीन के विकल्प के रूप में भारत, वियतनाम और अन्य देशों की ओर बढ़ी हैं। भारत यदि अपनी औद्योगिक नीतियों, आधारभूत संरचना, श्रम सुधार और तकनीकी क्षमता को मजबूत करता है तो वह वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बन सकता है। किंतु यदि भारत आवश्यक गति से सुधार नहीं कर पाया तो यह अवसर अन्य देशों के पास चला जाएगा। तकनीकी क्षेत्र में भी अमेरिका-चीन संबंधों का भारत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और रेयर अर्थ मिनरल्स नई शक्ति राजनीति के केंद्र बन चुके हैं। अमेरिका तकनीकी श्रेष्ठता बनाए रखना चाहता है जबकि चीन तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत इन दोनों के बीच एक तीसरे विकल्प के रूप में उभर सकता है, लेकिन इसके लिए अनुसंधान, नवाचार और शिक्षा में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। भारत के पास प्रतिभा है, लेकिन प्रतिभा को वैश्विक नेतृत्व में बदलने के लिए दीर्घकालिक दृष्टि चाहिए।

भू-राजनीतिक दृष्टि से भी यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संकटों पर अमेरिका और चीन की भूमिका निर्णायक है। यदि दोनों देशों के बीच समझ बढ़ती है तो सैन्य टकरावों की आशंका कम हो सकती है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर होंगे और तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देश के लिए यह अत्यंत लाभकारी स्थिति होगी। लेकिन यदि दोनों महाशक्तियाँ अपने प्रभाव विस्तार के लिए संकटों का उपयोग करती हैं तो विश्व अस्थिरता और बढ़ सकती है। भारत की विदेश नीति के लिए यह समय अत्यंत निर्णायक है। भारत को अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखते हुए चीन के साथ व्यावहारिक संबंधों का संतुलन बनाना होगा। साथ ही उसे वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों के नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका और मजबूत करनी होगी। जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने जिस वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की अवधारणा प्रस्तुत की थी, वह भविष्य की विश्व व्यवस्था का वैकल्पिक मॉडल बन सकती है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो अमेरिका और चीन जहाँ शक्ति संतुलन की राजनीति में उलझे हुए हैं, वहीं भारत सहअस्तित्व, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग की नीति पर चल रहा है। अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा शक्ति प्रदर्शन पर आधारित है जबकि भारत का दृष्टिकोण विकास, मानवीय मूल्यों और वैश्विक साझेदारी पर केंद्रित रहा है। यही भारत की विशिष्टता और शक्ति है।

आज दुनिया में यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि क्या अमेरिका और चीन मिलकर दुनिया को पुनः अपने प्रभाव क्षेत्र में बाँटने का प्रयास करेंगे? क्या छोटे देशों की भूमिका सीमित हो जाएगी? क्या फिर वही स्थिति बनेगी जब महाशक्तियाँ विश्व राजनीति को अपनी उँगलियों पर नचाती थीं? इन प्रश्नों के उत्तर भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि आज की दुनिया शीत युद्ध काल की दुनिया नहीं है। भारत, जापान, यूरोपीय संघ, ब्राजील, आसियान और अफ्रीकी देशों का बढ़ता प्रभाव विश्व व्यवस्था को बहुध्रुवीय बनाए रखने में सक्षम है। भारत को इस बदलती परिस्थिति में अपने संकल्पों को सुदृढ़ करना होगा, विकास के नए मानक गढ़ने होंगे और अपनी रणनीतिक क्षमता को विस्तार देना होगा। क्योंकि बदलती दुनिया में प्रश्न यह नहीं है कि अमेरिका और चीन क्या करेंगे, बल्कि यह है कि भारत स्वयं को किस ऊँचाई पर स्थापित करेगा।लेखक,पत्रकार एवं स्तंभकार है)।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

सफलता की कहानी : खुशियों की चाबी-मंत्री दयाल दास बघेल ने हितग्राहियों को सौंपे पीएम आवास के पक्के मकानों की चाबियां

सुशासन तिहार शिविर में ग्रामीणों के चेहरे पर दिखी खुशी, वर्षों का अपने घर का सपना हुआ साकार

बेमेतरा/मूक पत्रिका

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आज जनपद पंचायत नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत कटई में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने क्षेत्र के ग्रामीण हितग्राहियों को उनके नव निर्मित पक्के मकानों की चाबियां सौंपकर गृह प्रवेश की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर लाभार्थियों के चेहरों पर अपने सपनों का आशियाना मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। कार्यक्रम के दौरान खाद्य मंत्री श्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और बुनियादी सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि कोई भी परिवार कच्चे और असुरक्षित मकानों में रहने को मजबूर न हो।

कच्चे मकानों से मिली मुक्ति, पक्के घरों में शुरू हुई नई जिंदगी-वर्षों से कच्चे मकानों में जीवनयापन कर रहे ग्रामीण परिवारों के लिए यह दिन किसी उत्सव से कम नहीं रहा। जैसे ही हितग्राहियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी गईं, पूरे परिसर में खुशी और भावुकता का माहौल बन गया। कई हितग्राहियों ने बताया कि बरसात के दिनों में कच्चे मकानों में रहना बेहद कठिन होता था, लेकिन अब पक्के मकान मिलने से उनका परिवार सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेगा। एक लाभार्थी ने भावुक होकर कहा आज मेरा खुद के पक्के घर का सपना सच हो गया। अब हमारा परिवार सुरक्षित और खुश है। सरकार ने हमें नई जिंदगी दी है।

सुशासन तिहार बना जनकल्याण और विश्वास का माध्यम-सुशासन तिहार शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। शिविर में अधिकारियों द्वारा योजनाओं के त्वरित निराकरण, जनसमस्याओं के समाधान और पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई। मंत्री श्री बघेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए।

÷सबका सपना — घर हो अपना÷ का सपना हो रहा साकार-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में हजारों परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना से गरीब परिवारों को न केवल सुरक्षित आवास मिल रहा है, बल्कि उनके जीवन स्तर, सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास में भी सकारात्मक बदलाव आ रहा है। ग्राम पंचायत कटई में आयोजित यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास और जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

जन्मोत्सव बना सेवा और संवेदनाओं का प्रतीक

वृद्धा अनाथ आश्रम पहुंचे पूर्व संसदीय सचिव चन्द्रदेव राय, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर हुए भावुक

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

सारंगढ़ बिलाईगढ़ आमतौर पर जन्मदिन समारोह जहां भव्य आयोजनों और उत्सवों तक सीमित रह जाते हैं, वहीं पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक चन्द्रदेव राय ने अपने जन्मोत्सव को सेवा, संवेदना और सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सारंगढ़ जिला मुख्यालय स्थित वृद्धा अनाथ आश्रम पहुंचकर वृद्ध माताओं एवं पिता तुल्य बुजुर्गों के बीच जन्मोत्सव मनाया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

आश्रम परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आत्मीयता, सम्मान और भावनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। बुजुर्गों के बीच पहुंचे चन्द्रदेव राय ने उनसे आत्मीय संवाद किया, उनका कुशलक्षेम जाना तथा फल, मिठाई एवं आवश्यक सामग्री का वितरण किया। इस दौरान कई क्षण भावुक कर देने वाले रहे। राय ने कहा कि आज का दिन उनके जीवन के सबसे स्मरणीय एवं भावुक पलों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि जिन माता-पिता ने अपने पूरे जीवन परिवार और समाज के लिए समर्पित कर दिया, उन्हीं में से कई बुजुर्ग आज अकेलेपन का जीवन जीने को विवश हैं। ऐसे बुजुर्गों के बीच समय बिताना आत्मिक संतोष और मानवीय जिम्मेदारी का एहसास कराने वाला अनुभव है। उन्होंने पूर्व सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सारंगढ़ को नवीन जिले के रूप में मिली पहचान क्षेत्र के विकास की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। साथ ही जिला प्रशासन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वृद्धा आश्रम की स्थापना समाज सेवा और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में सराहनीय पहल है।

कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी, पत्रकार बंधु, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल को समाज के लिए सकारात्मक संदेश देने वाला कदम बताया। जन्मोत्सव के इस अनूठे आयोजन ने यह संदेश दिया कि सच्चा उत्सव वही है, जो समाज के जरूरतमंद और उपेक्षित लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सके।

खरसिया के लॉजों में कथित अनैतिक गतिविधियों की चर्चा, कार्रवाई की मांग तेज

खरसिया/मूक पत्रिका

नगर में संचालित कुछ लॉजों एवं किराए के ठिकानों में कथित रूप से अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की चर्चाओं ने शहर का माहौल गर्मा दिया है। स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं व्यापारिक वर्ग के लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियां लगातार जारी हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र का वातावरण प्रभावित हो रहा है नगरवासियों का कहना है कि देर रात बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ने से लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। विशेषकर युवा पीढ़ी पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभाव को लेकर अभिभावकों एवं सामाजिक संगठनों ने चिंता व्यक्त की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। सामाजिक संगठनों ने पुलिस प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि नगर के सभी लॉज, होटल एवं किराए के ठिकानों की नियमित जांच कराई जाए। साथ ही जिन स्थानों पर अवैध गतिविधियों की पुष्टि हो, वहां सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि शहर की सामाजिक व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनी रहे। नागरिकों ने यह भी कहा कि लंबे समय से शिकायतें सामने आने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। कई संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो जनजागरूकता अभियान एवं आंदोलन किया जाएगा। इधर प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस एवं संबंधित विभाग को दें, ताकि समय पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

इंद्रावती पार कर स्वास्थ्य टीम पहुंची नूगुर, 642 ग्रामीणों की जांच

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। जिले के अंदरूनी और दुर्गम क्षेत्र नूगुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम इंद्रावती नदी पार कर ग्रामीणों तक पहुंची और विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर 642 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। लंबे समय तक नक्सल प्रभाव और भौगोलिक कठिनाइयों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से दूर रहे इस इलाके में अब ग्रामीणों का भरोसा स्वास्थ्य विभाग पर बढ़ने लगा है। कलेक्टर श्री विश्वदीप के मार्गदर्शन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में विकासखंड भैरमगढ़ अंतर्गत नूगुर, हिंगमेटा और हुर्रागवाली गांवों में यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों की जांच कर दवाइयों का वितरण किया और गंभीर मरीजों को आगे उपचार के लिए सलाह दी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक उप स्वास्थ्य केंद्र नूगुर विकासखंड मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए टीम को लगभग दो किलोमीटर चौड़ी इंद्रावती नदी पार करनी पड़ी। शिविर के दौरान ग्रामीणों की एनसीडी स्क्रीनिंग, बुखार और त्वचा संबंधी बीमारियों की जांच की गई। साथ ही टीकाकरण और स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि पहले ग्रामीण स्वास्थ्य जांच और बच्चों के टीकाकरण से कतराते थे, लेकिन अब लोग खुद आगे आकर जांच करा रहे हैं। इस अभियान में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर दीपक कुमार देवांगन, सेक्टर सुपरवाइजर के.पी. बीरवंश, अतुल कुशवाह, राजू पुगेठी, रीता फुलमादरी, दीप्ति खेस, आकृति भगत और मनोरमा तोकल ने सक्रिय भूमिका निभाई।

इंद्रावती पार कर पहुंची स्वास्थ्य टीम
नूगुर क्षेत्र मुख्यालय से करीब 90 किमी दूर
टीम को लगभग 2 किमी चौड़ी इंद्रावती नदी पार करनी पड़ी
नूगुर, हिंगमेटा और हुर्रागवाली में लगे स्वास्थ्य शिविर
कुल 642 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण
232 लोगों की एनसीडी स्क्रीनिंग
ग्रामीणों में टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच के प्रति बढ़ी जागरूकता

मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित होगी

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मिलेगा अवसर

बेमेतरा/मूक पत्रिका

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई 2026, रविवार को किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम कन्या विद्यालय, बेमेतरा में आयोजित होगी। आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के निर्देशानुसार परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन कार्य की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसके तहत परीक्षा पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन कार्य के लिए प्रत्येक संस्था से दो-दो शिक्षकों के नाम मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारियों बेमेतरा, बेरला, साजा एवं नवागढ़ को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के प्राचार्यों एवं प्रधान पाठकों की बैठक आयोजित कर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। साथ ही पात्र विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सभी आवश्यक कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के अनुसार चेकलिस्ट के आधार पर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की सूची तैयार कर 30 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए उचित शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

मुख्यमंत्री की मंशानुरूप बेहतर सड़कें और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने निर्देश

- कार्य में विलंब पर एसडीओ पीडब्ल्यूडी अकलतरा को नोटिस जारी, हर 15 दिन में निर्माण कार्यों का समीक्षा बैठक लेंगे कलेक्टर

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में लोक निर्माण विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर जिले में संचालित सड़कों एवं भवन निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता तथा समय-सीमा की गहन समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने प्रगतिरत, निविदा स्तर एवं तकनीकी स्वीकृति स्तर के सभी निर्माण कार्यों की बिंदुवार जानकारी ली तथा कार्यों में अनावश्यक विलंब पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता और समय-सीमा को सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप जिले में बेहतर सड़क संपर्क, गुणवत्तापूर्ण निर्माण एवं समय पर कार्य पूर्ण करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा विलंब होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने एसडीओ पीडब्ल्यूडी अकलतरा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में स्वीकृत सड़कों से संबंधित प्रस्तावों की भी समीक्षा की। उन्होंने कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि जनसामान्य की मांग एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रेषित करें, ताकि उन्हें आगामी बजट में शामिल कराया जा सके। भूअर्जन से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि संबंधित एसडीएम से समन्वय स्थापित कर भूअर्जन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराई जाए, ताकि निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो और परियोजनाओं को समय पर गति मिल सके। कलेक्टर ने कहा कि जिले में चल रहे सभी प्रमुख निर्माण कार्यों का प्रत्येक 15 दिन में बैठक लेकर समीक्षा करेंगे।लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया ग्राम औराईकला स्थित नाला पर नक्टा पुल निर्माण कार्य, पचेड़ा से कनई सड़क निर्माण कार्य, पकरिया से रिवापार तक पक्की सड़क निर्माण कार्य, बछौद पहुंच मार्ग (चंदनिया तक), चंदनिया से ढोरला मार्ग, बलौदा लाईनपारा से ढोरला मार्ग, धाराशिव से रोगदा मार्ग तथा मुड़पार (ब) से मुरली गांव तक मार्ग निर्माण प्रगतिरत हैं। वहीं ग्राम बेलटूकरी से खैजा नहर पार तक सड़क निर्माण कार्य, नेवराबंद से बारगांव मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बैठक में कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर कहा कि सड़क एवं भवन निर्माण में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट करने तथा निर्माण स्थलों का सतत निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के ईई ने बताया कि निविदा प्रक्रिया अंतर्गत पीथमपुर ग्रामीण मार्ग मजबूतीकरण कार्य, बीटीआई चौक से खोखसा आरओबी रोड, अकलतरा से जर्वे (खोड़ फाटक) मार्ग, अर्जुनी से करूमहु मार्ग, बनारी पहुंच मार्ग, बोड़सरा-सिवनी मार्ग, जांजगीर बाईपास मार्ग, जांजगीर -केरा -शिवरीनारायण मार्ग, एनएच-49 से अर्जुनी पहुंच मार्ग तथा तरौद-तागा-धाराशिव मुख्य जिला मार्ग निर्माण कार्य, कलेक्टोरेट रोड अप्रोच रोड नवीनीकरण, सिविल कोर्ट जांजगीर अप्रोच रोड नवीनीकरण कार्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जोगी-मुरली मार्ग पर कंजी नाला पुल निर्माण कार्य व बंसुला से कपिस्दा तक मार्ग प्रक्रिया में है।

कृषि वैज्ञानिकों ने गांव-गांव पहुंचकर किसानों को दी आधुनिक तकनीक, जैविक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग की सलाह

15 दिवसीय विकसित कृषि संकल्प अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न

5800 से अधिक किसानों तक पहुंची वैज्ञानिक खेती की जानकारी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले में कृषि के सतत विकास एवं किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित 15 दिवसीय ÷विकसित कृषि संकल्प अभियान÷ का सफलतापूर्वक समापन 20 मई 2026 को हुआ। यह अभियान 5 मई से प्रारंभ होकर जिले के चारों विकासखंडों की चयनित 96 ग्राम पंचायतों में संचालित किया गया। अभियान के अंतिम दिवस पर कृषि वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों की टीम ग्राम मरका, बाराडेरा, कीर्तिपुर, चेतुआ, बुचीपुर, बोरदेही, नवागांवकला एवं सोमईकला पहुंची, जहां किसानों से प्रत्यक्ष संवाद कर उन्हें खरीफ फसलों की उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को खरीफ मौसम हेतु वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से अवगत कराना, संतुलित रासायनिक उर्वरक उपयोग के प्रति जागरूक करना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित खेती को बढ़ावा देना तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना रहा। इसके साथ ही आधुनिक कृषि यंत्रों, उपकरणों एवं ड्रोन तकनीक के उपयोग और प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों से परिचित कराया गया। अभियान के दौरान फसल बीमा, जल संरक्षण, बीज उपचार एवं बीज उत्पादन, फसल चक्र परिवर्तन, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती तथा प्राकृतिक कृषि तकनीकों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। इस व्यापक अभियान के सफल संचालन में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा, कृषि महाविद्यालय ढोलिया, उद्यानिकी विभाग, मछलीपालन विभाग, पशुपालन विभाग, फसल बीजा, बीज उत्पादक संस्थाओं एवं पंचायत विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभियान के दौरान कृषि वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों ने कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा, तकनीकी मार्गदर्शन एवं संगोष्ठियों के माध्यम से 5804 से अधिक किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया। किसानों की रासायनिक खाद से जुड़ी वर्तमान समस्याओं, हरी खाद एवं नील हरित काई के उपयोग से समाधान, कृषि नवाचारों एवं तकनीकी आवश्यकताओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा के वैज्ञानिक डॉ. जीतेन्द्र कुमार जोशी ने बेरला विकासखंड के किसानों को हरी खाद एवं नील हरित काई के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने धान रोपा यंत्र, पैडी ड्रम सीडर एवं धान प्लांटर मशीन द्वारा सीधी बुआई की आधुनिक तकनीकों पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही किसानों को उन्नत धान किस्मों के चयन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनाने तथा फसल अवशेषों को जलाने के बजाय बेलर मशीन से संग्रहित कर अतिरिक्त आय अर्जित करने की सलाह दी। इसी प्रकार कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा के वैज्ञानिक डॉ. लव कुमार साहू ने साजा विकासखंड के किसानों को उद्यानिकी फसलों की आधुनिक खेती, टपक एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के उपयोग तथा जलवायु आधारित उन्नत किस्मों के चयन की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के माध्यम से टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि अपनाने के लिए प्रेरित किया। कृषि वैज्ञानिक श्रीमती रजनी धर्मेंद्र अगाशे एवं श्री डोमन सिंह टेकाम ने बेमेतरा विकासखंड में आयोजित प्रशिक्षण एवं कृषक संगोष्ठियों के दौरान किसानों को मिट्टी की सेहत एवं संतुलित उर्वरक उपयोग के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी दी कि मिट्टी परीक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार जिले की कृषि भूमि में फॉस्फोरस एवं पोटाश की मात्रा मध्यम से उच्च स्तर पर है, जबकि नत्रजन एवं जैविक कार्बन की मात्रा कम पाई गई है। लगातार यूरिया एवं डीएपी के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता एवं पर्यावरण दोनों प्रभावित हो रहे हैं। किसानों को जैविक एवं जैव उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, ब्रह्मास्त्र, वाफसा एवं आच्छादन जैसी प्राकृतिक खेती तकनीकों की उपयोगिता समझाई। साथ ही एजोस्पिरिलम, एजेटोबैक्टर, माइकोराइजा, पीएसबी, केएसबी एवं एनपीके कंसोर्टियम जैसे जैव उर्वरकों के उपयोग की जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री तोषण कुमार ठाकुर ने किसानों को डीएपी एवं यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, टीएसपी, एसएसपी एवं एनपीके कंसोर्टियम के समन्वित उपयोग की सलाह दी। उन्होंने कहा कि संतुलित एवं वैज्ञानिक खेती अपनाकर किसान उत्पादन लागत कम करने के साथ बेहतर उत्पादन एवं आय प्राप्त कर सकते हैं।

संक्षिप्त समाचार

झूठी शिकायत सिद्ध होने पर भाजपा नेता अमर सुल्तानिया के खिलाफ दर्ज अपराध खारिज

काउंटर केस दर्ज कराने वालों पर अब होगी कड़ी कार्रवाई, एसपी ने दिए निष्पक्ष जांच के निर्देश

मूक पत्रिका/जांजगीर-चांपा। जिले के चौकी नैला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुड़पार में भाजपा नेता अमर सुल्तानिया के विरुद्ध दर्ज काउंटर अपराध को पुलिस ने निष्पक्ष जांच के बाद झूठा पाए जाने पर खारिज कर दिया है। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शिकायतकर्ता ने अपने विरुद्ध दर्ज मूल अपराध से बचने के लिए तथ्य छुपाकर झूठी जानकारी देकर काउंटर अपराध दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के निर्देश पर मामले की गंभीरता से जांच कराई गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगिता बाली खापर्डे के मार्गदर्शन में वैधानिक कार्रवाई की गई। ग्राम मुड़पार में अमर सुल्तानिया का इथेनॉल प्लांट निर्माणाधीन है। पंचायत से प्रस्ताव पारित होने एवं सरपंच से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद रामसागर बांधा तालाब से मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा था। इसी दौरान गांव के प्रहलाद गिर गोस्वामी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा निजी स्वार्थ के चलते बार-बार कार्य को रोकने का प्रयास किया जा रहा था। दिनांक 18 मई 2026 की रात्रि लगभग 10 बजे आरोपियों द्वारा मौके पर पहुंचकर उत्खनन कार्य रोकते हुए अमर सुल्तानिया के कर्मचारियों लोचन प्रसाद मिरी एवं लोकेश कुमार भैना के साथ हाथ-मुक्का व डंडे से मारपीट की गई। इस संबंध में प्रहलाद गिर गोस्वामी एवं अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अगले दिन जब आरोपियों को अपने विरुद्ध अपराध दर्ज होने की जानकारी मिली, तब उन्होंने चौकी नैला में अमर सुल्तानिया एवं उनके गार्ड पर मारपीट व गाली-गलौज का आरोप लगाते हुए काउंटर अपराध दर्ज कराया। पुलिस द्वारा घटनास्थल, आसपास के लोगों, वायरल वीडियो फुटेज एवं दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि अमर सुल्तानिया या उनके किसी कर्मचारी द्वारा कोई मारपीट अथवा गाली-गलौज नहीं की गई। वीडियो फुटेज में भी आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता ने घटना वाले दिन दिए गए लिखित आवेदन में मारपीट या गाली-गलौज का कोई उल्लेख नहीं किया था। इससे यह स्पष्ट हुआ कि अपने विरुद्ध दर्ज अपराध से बचने के उद्देश्य से झूठी शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अमर सुल्तानिया एवं उनके गार्ड के विरुद्ध दर्ज अपराध को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वालों के विरुद्ध उन्हीं धाराओं में पृथक से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दशगात्र कार्यक्रम हेतु शोक समाचार

छिन्दगांव - अत्यंत दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत छिन्दगांव, चालानपारा निवासी स्वर्गीय महादेई बघेल जी का दिनांक 12 मई 2026 को लगभग 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अपने भरे-पूरे परिवार एवं प्रियजनों को छोड़कर परमधाम को प्रस्थान कर गईं।

स्वर्गीय महादेई बघेल जी, श्री भारत सिंह बघेल जी की पूज्य माताजी एवं पत्रकार पवन कुमार नाग की मामी थीं। उनके निधन से परिवार एवं क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है।

स्वर्गीय आत्मा की शांति हेतु दशगात्र/दशा कार्यक्रम दिनांक 24 मई 2026, दिन रविवार को आयोजित किया गया है, जिसमें सभी इष्ट मित्र, समाजजन एवं शुभचिंतकों से उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित करने की विनम्र अपील की गई है।

शोकाकुल परिवार:
बड़े पुत्र - लेखन बघेल
मझले पुत्र - नरसिंग बघेल
छोटे पुत्र - भारत सिंह बघेल
एवं समस्त बघेल परिवार

ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिवार को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

क्लासिक लेजेंड्स ने जावा, येज्दी और बीएसए डीलरशिप नेटवर्क पर 9 दिवसीय लेजेंड्स केयर कैंप की शुरुआत की

मुंबई: ग्राहकों की संतुष्टि और बिक्री के बाद के अनुभव को और बेहतर बनाने के अपने लगातार प्रयासों के तहत, क्लासिक लेजेंड्स ने देशव्यापी सर्विस पहल लेजेंड्स केयर कैंप शुरू करने की घोषणा की है। यह 9 दिवसीय सर्विस कैंप 23 मई से 31 मई 2026 तक कंपनी के सभी आधिकारिक जावा, येज्दी और बीएसए डीलरशिप नेटवर्क पर आयोजित किया जाएगा। यह सर्विस कैंप देश के कई शहरों में आयोजित किया जा रहा है। इसमें ग्राहकों को उनके वाहनों की पूरी जांच के साथ-साथ सर्विस, स्पेयर पार्ट्स, लेबर और जेन्युइन एक्सेसरीज पर खास फायदे मिलेंगे। इस पहल के तहत, कंपनी के अनुभवी और प्रशिक्षित मैकेनिक मोटरसाइकिलों की बारीकी से 72-पॉइंट जांच करेंगे। इसमें इंजन का परफॉर्मेंस, ब्रेक, क्लच, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, टायर, सस्पेंशन, बैटरी की सेहत और गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन जैसे जरूरी हिस्सों की जांच की जाएगी, ताकि बाइक चलाने में बेहतरीन परफॉर्मेंस और पूरी सुरक्षा मिल सके। इस कैंप के दौरान आधिकारिक डीलरशिप पर जाने वाले ग्राहकों को समय-समय पर होने वाली मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और जेन्युइन एक्सेसरीज पर विशेष ऑफर भी दिए जाएंगे।

चार वर्षों से कम वेतन भुगतान का क्षतिपूर्ति के साथ भुगतान हो

कोमलदेव अस्पताल में कर्मचारियों के शिशुओं के लिए झुला घर खोलने की मांग

दैनिक मूक पत्रिका/ विक्रम ठाकुर/ कांकेर :- कांकेर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत कोमलदेव अस्पताल में कार्यरत स्थाई एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रेच (झुला घर) खोलने की मांग आज अस्पताल में कार्यरत प्लेसमेंट सफाई और सुरक्षा कर्मियों श्रम पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किया है।

आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में प्लेसमेंट कर्मचारियों के नेता अन्नू वाल्मीकि ने बताया कि राजमिस्त्री मजदूर रेजा कुली एकता यूनियन के बैनर तले आज यह ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भारी संख्या में कर्मचारी जिसमें कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या अधिक है लेकिन इन कर्मचारियों के शिशुओं की देखरेख के लिए कोई क्रेच या झुला घर तक नहीं है।

कर्मचारी नेता ने कहा कि अस्पताल में भारी संख्या में महिला सफाई, सुरक्षा कर्मचारी के साथ नर्सें भी कार्यरत है लेकिन इनके शिशुओं के लिए कोई झुला घर नहीं होना अस्पताल प्रबंधन की अमानवीय चेहरा ही उजागर होता है। बाल्मीकि ने कहा कि श्रम कानून के नियम के मुताबिक जिस संस्था में 50 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है वहां झुला घर होना अनिवार्य है। अस्पताल में झुला घर नहीं होने के कारण महिला कर्मचारियों को अपने छोटे छोटे शिशुओं को साथ लेकर कार्य पर आने को विवश है यहां तक कि रात्रि के पाली में भी महिला कर्मचारी को अपने शिशुओं को साथ में लेकर कार्य करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि आज श्रम पदाधिकारी को प्लेसमेंट कर्मचारियों के कम वेतन भुगतान की बात भी रखा गया जिस पर श्रम पदाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को कहा कि श्रम विभाग इस दिशा में संबंधित ठेकेदार पर कानूनी कार्यवाही करने की प्रक्रिया में अग्रसर है और उन्होंने कर्मचारियों को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल ने श्रम पदाधिकारी से से पिछले चार वर्षों से कर्मचारियों को जो कम वेतन भुगतान कर रहा था वो पूरी राशि ठेकेदार या मुख्य नियोक्ता से वसूल कर ब्याज सहित कर्मचारियों को भुगतान किए जाने की मांग की जिस पर श्रम पदाधिकारी ने कहा जल्द ही उचित कार्यवाही होगी। आज के प्रतिनिधिमंडल में अन्नू वाल्मीक, सरिता कोड़ोपी, प्रिया पटेल, लता भास्कर, निर्मला ठाकुर, कुंभकर्ण, प्रीति मंडावी, देवचंद भास्कर मौजूद थे।

खाद विक्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण, 5 दुकानदारों को नोटिस जारी

मूक पत्रिका/सारंगढ़ बिलाईगढ़, 21 मई 2026/वैश्विक संकट को देखते हुए समय पर जिले के किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद उपलब्ध कराने और खाद की कालाबाजारी एवं नकली खाद के विक्रय पर रोक लगाने हेतु पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर आशुतोष श्रीवास्तव, उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में उर्वरक निरीक्षक के द्वारा बुधवार को जिले के कई सहकारी, निजी विक्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उर्वरक निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता और बीटीएम मायाशंकर जोल्हे एवं प्रकाश कुमार थवाईत उपस्थित रहे। विकासखण्ड बिलाईगढ़ अंतर्गत मेसर्स आनंद ट्रेडर्स सरसींवा, प्रकाश ट्रेडर्स पेण्ड्रावन, धनलक्ष्मी ट्रेडर्स जोरापाली, प्रमोद कृषि केन्द्र, राहुल हार्डवेयर भटगांव, पुष्पराज केशरवानी भटगांव, मेलाराम कृषि केन्द्र दुमहानी का निरीक्षण किया गया। जिसमें एफ्सीओ का उल्लंघन करते पाये जाने पर कार्यवाही करते हुए मेसर्स आनंद ट्रेडर्स सरसींवा, धनलक्ष्मी टेडर्स जोरापाली, पुष्पराज केशरवानी भटगांव, राहुल हार्डवेयर भटगांव, साहू खाद भण्डार, पवनी खाद विक्रय केन्द्रों को नोटिस जारी किया गया।

सुशासन तिहार-2026 : विकासखण्ड बेमेतरा के ग्राम चोरभट्ठी, बेरला के ग्राम पंचायत आनंदगांव एवं विकासखंड साजा के ग्राम पंचायत तेन्दूभाठा ,नवागढ़ के नगर पंचायत में समाधान शिविर आज

मूक पत्रिका/बेमेतरा/- सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत 22 मई को जनपद पंचायत बेमेतरा के ग्राम पंचायत चोरभट्ठी (शा. पूर्व माध्यमिक शाला), जनपद पंचायत बेरला के ग्राम पंचायत आनंदगांव तथा विकासखंड साजा के ग्राम पंचायत तेन्दूभाठा (प्राथमिक शाला), नवागढ़ के नगर पंचायत वार्ड नं. 01 से 05 तक वार्ड क्र. 15 सतनाम भवन नवागढ में समाधान शिविर आयोजित किया गया है।

ग्राम चोरभट्ठी क्लस्टर में ग्राम बावामोहतरा, भोइनाभाठा, पिपरभट्ठा, चोरभट्ठी, ताला, बीजाभाठ, जेवरी, अमोरा, मटका, बसनी, पथर्रा, जौंग, जेवरा, बहिंगा, जिया, कुसमी, बहेरा खुर्द एवं नवागांव खुर्द ग्राम पंचायत शामिल हैं।

इसी प्रकार ग्राम आनंदगांव क्लस्टर में ग्राम खर्रा, कुम्ही, देवरी, बहेरा, जामगांव, सुरहोली, पाहदा, आनंदगांव, चेटूवा, अछोली, बारगांव, जमघट, बलौदी कला, तेलगा, भरदा, मुड़पार कला, खुडमुड़ा, लावातरा, सिलघट एवं सिंगदेही ग्राम पंचायतों के लिए शिविर आयोजित किया गया है। विकासखंड साजा के ग्राम पंचायत तेन्दूभाठा क्लस्टर में कंदई, रौद्रा, सेमरिया, तेन्दुवा, महीदही, बीजा, घोटवानी, बोड़, डोंगीतराई, मोहगांव, मौहाभाठा, तेन्दूभाठा, कांचरी, परसबोड़, माटरा, हरडुवा, अकलवारा एवं राखी ग्राम पंचायत शामिल हैं।

शिविर का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 03 बजे तक निर्धारित किया गया है। समाधान शिविर में विभिन्न विभागों की योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा तथा प्राप्त आवेदनों का यथासंभव निराकरण किया जाएगा। शिविर में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने ग्रामीण जनों से शिविर में उपस्थित होकर अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है।

सैमसंग ने भारत में 2026 विज़न एआई टीवी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया

सैमसंग ने घोषणा की है कि भारत में ग्राहक अब कंपनी के नए 2026 विजन एआई टेलीविज़न के लिए अपनी दिलचस्पी दर्ज करा सकते हैं। कंपनी इस नई टीवी सीरीज़ को इसी महीने लॉन्च करने वाली है। सैमसंग के नए विजन एआई टीवी एडवांस फीचर्स और अत्याधुनिक तकनीक के साथ आएंगे, जो व्यूइंग अनुभव को और बेहतर बनाएंगे। कंपनी ने बताया कि 2026 में वह अपनी विजन एआई कम्पेनियन यानी वीएसी सुविधाओं का विस्तार 4K यूएचडी और उससे ऊपर की टीवी रेंज में करेगी, जो टीवी अनुभव के केंद्र में एआई को लाने की उसकी व्यापक रणनीति को दर्शाता है। इससे एआई आधारित व्यूइंग को ज्यादा कैटेगरी, स्क्रीन साइज़ और अलग-अलग उपभोक्ता जरूरतों तक पहुंचाया जा सकेगा। सैमसंग पिछले 20 वर्षों से ग्लोबल नंबर-1 टीवी ब्रांड बना हुआ है। यह सफलता प्रीमियम और अल्ट्रा-लार्ज स्क्रीन इनोवेशन के प्रति सैमसंग की प्रतिबद्धता और अत्याधुनिक एआई-पावर्ड टीवी की वजह से मिली है।

जियोहॉटस्टार और कलर्स लेकर आए 'भोजपुरी बवाल' भारत की पहली प्रीमियम सेलिब्रिटी फॉलो-रियलिटी सीरीज़, जो देश की मिट्टी और दिल की धड़कन को देगी नया मंच

पवन सिंह, दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव जैसे भोजपुरी मनोरंजन जगत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स से सजा यह शो दर्शकों को उनके वास्तविक जीवन की एक अभूतपूर्व और बेहद करीब से झलक दि।

जित मुंबई:-भोजपुरी मनोरंजन आज भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते और बेहद लोकप्रिय क्षेत्रीय उद्योगों में से एक बन चुका है। अपने संगीत, सिनेमा और बड़े सितारों के दम पर इस इंडस्ट्री ने न केवल देश के हृदयस्थल बल्कि उससे बाहर भी करोड़ों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। इसी सांस्कृतिक लोकप्रियता को नए आयाम देते हुए भोजपुरी मनोरंजन जगत के सबसे बड़े सितारे अब कैमरों की चमक-दमक से बाहर निकलकर दर्शकों के सामने अपनी ज़िंदगी की अब तक की सबसे बेबाक और अनफ़िल्टर्ड झलक पेश करने के लिए तैयार हैं। जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होने और कलर्स टीवी पर प्रसारित होनेवाली यह सीरीज़ दर्शकों को मंच, पर्दे और शोहरत की दुनिया से आगे ले जाकर भोजपुरी मनोरंजन जगत के सबसे बड़े सितारों पवन सिंह, दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव के निजी और पेशेवर जीवन की अनदेखी झलक दिखाएगी। पारंपरिक रियलिटी शोज़ से अलग, यह सीरीज़ पहली बार एक अनोखे 'फॉलो रियलिटी' फॉर्मेट को पेश कर रही है, जिसमें न कोई टास्क होगा, न एलिमिनेशन और न ही किसी तरह का बनावटी ड्रामा। इसके बजाय, कैमरे इन सितारों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खामोश गवाह बनेंगे और दर्शकों को उन चेहरों के पीछे छिपे असली इंसान से रूबरू कराएंगे। शो में शोहरत, फैन फॉलोइंग, पारिवारिक दबाव, महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा, जश्न, विवाद और सुपरस्टार बनने के पीछे की लगातार मेहनत जैसे हर पहलू को बेहद करीब और वास्तविक अंदाज़ में दिखाया जाएगा। 'भोजपुरी बवाल' इन सभी रंगों को पूरी सच्चाई और भावनाओं के साथ दर्शकों तक पहुँचाने का वादा करता है।

घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जियोस्टार में हिंदी एवं अंग्रेज़ी मनोरंजन व्यवसाय (स्ट्रीमिंग, टीवी और स्टूडियोज़) के प्रमुख आलोक जैन ने कहा , ट्रुजियोहॉटस्टार भारत में अनस्क्रिप्टेड प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा मंच है, जहाँ दर्शकों को नॉन-फिक्शन कहानियों की सबसे व्यापक श्रृंखला देखने को मिलती है। हमने लगातार नए फॉर्मेट्स के साथ प्रयोग करते हुए इस पहचान को मज़बूत किया है चाहे वह कैप्टिव रियलिटी हो, कॉमेडी, टैलेंट आधारित शोज़ हों या रिश्तों और मानवीय भावनाओं से जुड़ी कहानियाँ। 'भोजपुरी बवाल' के साथ हम इस नवाचार को एक नए आयाम पर ले जा रहे हैं। यह अपनी तरह का पहला 'फॉलो रियलिटी' फॉर्मेट है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों की असली ज़िंदगी को दर्शकों के सामने पेश करेगा। भोजपुरी मनोरंजन हिंदी पट्टी की सबसे जीवंत और प्रभावशाली सांस्कृतिक ताकतों में से एक है, और यह शो उसकी भव्यता, भावनाओं और वास्तविकता को राष्ट्रीय स्तर के व्यापक दर्शकों तक पहुँचाएगा सिर्फभोजपुरी दर्शकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए। सेलिब्रिटी दुनिया की खास पहुंच और भावनात्मक वास्तविकता के अनोखे संगम के साथ, 'भोजपुरी बवाल' दर्शकों को उन सितारों की ज़िंदगी की बेहद करीबी, बेबाक और गहराई से जुड़ी झलक दिखाने का वादा करता है, जिन्होंने भारत की सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय मनोरंजन इंडस्ट्रीज़ में से एक को नई पहचान दी है। 'भोजपुरी बवाल' जल्द ही विशेष रूप से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा और कलर्स टीवी पर प्रसारित किया जाएगा।*

सारंगढ़ में 22 मई को जनजातीय कारीगर हैंडीक्राफ्ट मेला प्रदर्शनी

जनजातीय कारीगर को जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लाना अनिवार्य

सारंगढ़ बिलाईगढ़/ जनजातीय गरिमा उत्सव कार्यक्रम अंतर्गत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ के जनजातीय कारीगरों के द्वारा हस्तनिर्मित (हैंडीक्राफ्ट) वस्तुओं के विक्रय एवं प्रदर्शनी हेतु मेला का आयोजन 22 मई 2026 को प्रात: 11 बजे से शाम 05 बजे तक साहू धर्मशाला परिसर रानीसागर सारंगढ़ में किया जा रहा है। जनजातीय वर्ग के कारीगरों को अपने हस्तनिर्मित वस्तुओं के प्रदर्शन एवं विकय हेतु आयोजित मेले में आमंत्रित किया गया है। जनजातीय कारीगर को अपने साथ जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति साथ में लाना अनिवार्य है।

सारंगढ़ और धाराशिव में 22 मई को होगा सुशासन शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़/ सुशासन तिहार शिविर सारंगढ़ नगरपालिका के वार्ड 5, 6, 7, 8, 15 के लिए जेलपारा रंगमंच में और बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम धाराशिव के स्कूल परिसर में 22 मई को सुबह 11 बजे से अपरान्ह 3 तक आयोजन किया जाएगा, जिसमें ग्राम बांसउरकुली, भण्डोरा, देवरबोड, खजरी, खैरझिटी, खुरसुला, पण्डरीपानी, सुतीउरकुली बेलटिकरी, बिसनपुर, छपोरा, चुरेला, धाराशिव, डोकरीडीह, डुरूमगढ़, गोविन्दवन, रमतला शामिल हैं। शिविर में नागरिक अपनी मांग, सुझाव और शिकायत प्रशासन को दे सकते हैं।

सारंगढ़ ब्लॉक के ग्राम अमलीडीपा और तिलाईदादर में 22 मई को होगा धरती आबा शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़/ कर्मयोगी अभियान जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान और पीएम जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में धरती आबा का शिविर सारंगढ़ ब्लॉक के ग्राम अमलीडीपा और तिलाईदादर में 22 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजन किया जाएगा, जिसमें कृषि एवं अन्य विभागों के फील्ड अधिकारी कर्मचारी, पटवारी, सरपंच, पंचायत सचिव, मितानिन, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका शामिल होंगे। इस दौरान सभी फील्ड अधिकारी कर्मचारी अपने विभाग की जानकारी एवं सेवाएं देंगे।

सुशासन शिविर मंच में अधिकारी दे रहें योजनाओं की जानकारी और स्टॉल से लाभ

मंच से लखपति दीदीयों ने साझा की अपनी सफलता की कहानी

कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग को जिले में कुपोषण से मुक्त करने के लिए प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए

मूक पत्रिका/ सारंगढ़ बिलाईगढ़, 21 मई 2026/ सारंगढ़ ब्लॉक के ग्राम उच्चभिठी के हाईस्कूल परिसर में सुशासन तिहार शिविर का आयोजन सुबह 11 बजे से अपरान्ह 3 तक किया गया। शिविर में ग्राम कोसीर, भांठागांव, बटाउपाली अ, मुड़वाभांठा, पाट, सिलियारी, रींवापार, कुम्हारी, लेन्ध्रा, गाताडीह, चांटीपाली, मुड़पार बड़े, सिरोली, खम्हारडीह, साल्हे, बोरिदा, उच्चभिठी, कलमी, परसकोल के ग्रामीणों ने प्रशासन को 829 आवेदन मांग के और 4 शिकायत के प्रस्तुत किए। शिविर में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू, विधायक उत्तरी जांगड़े, पूर्व विधायक केराबाई मनहर, कामदा जोल्हे के आतिथ्य में शिविर सम्पन्न हुआ। पशुधन, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व और समाज कल्याण विभाग से त्वरित लाभ दिया गया। अतिथियों ने हितग्राहियों को मछली जाल, प्रशस्ति पत्र, बी 1, किसान पुस्तिका, पीएम आवास चाबी, शौचालय

स्वीकृति, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, छड़ी, कान की मशीन, 5 स्व सहायता समूह को 6 लाख के चेक आदि वितरित किया। विभिन्न विभाग के अधिकारियो ने योजनाओं की जानकारी दीं और स्टाल में योजना का लाभ लेने आये पात्र हितग्राहियों को लाभ दिए। इसी प्रकार बिहान स्व सहायता समूह की लखपति दीदीयों ने अपने सफलता की कहानी मंच से साझा की।

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने कहा कि, शिविर के सफल आयोजन के लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है। राज्य शासन के मंशा अनुरूप जिले के सभी गांव तक जिला प्रशासन के सभी अधिकारी शिविर के माध्यम से पहुंच रहें हैं। मांग और शिकायत के प्राप्त आवेदनों का निराकरण जिला और राज्य स्तर पर की जा रही है। कलेक्टर ने जिले को कुपोषण से मुक्त करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी अधिकारियो को निर्देश दीं कि वे कुपोषण मुक्त करने के क्षेत्र में प्रभावी कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक विभिन्न स्टॉल में जाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी लें और पात्र होने पर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत करें।

विधायक उत्तरी जांगड़े ने कहा कि छोटे छोटे काम के लिए जिला और जनपद पंचायत जाना पड़ता था, अब वह काम शिविर में होगा, ग्राम स्तर पर होगा। पूर्व विधायक केराबाई मनहर ने कहा कि राज्य शासन पीएम आवास, घर घर जल, आयुष्मान कार्ड आदि बुनियादी सुविधा का लाभ दे रही है। कामदा जोल्हे ने कहा कि कृषि विभाग का रासायनिक खाद की पर्याप्त व्यवस्था करें ताकि किसानों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिले में महानदी से पेयजल आपूर्ति के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।

पूर्व विधायक कामदा जोल्हे ने की मांग- पूर्व विधायक कामदा जोल्हे ने कहा कि कोसीर में कॉलेज खोलने के लिए बजट में आ गया है, कालेज खोलने का कार्य, कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल,बाल उद्यान, उप स्वास्थ्य केंद्र का सेटअप और एम्बुलेंस उपलब्ध कराएं। इस क्षेत्र में पीएम ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से खुरबेना बरदुला, बरदुला जसपुर, खुरबेना गोपालभौना, उच्चभीठी से कोसीर मार्ग का निर्माण किया जाए। साथ ही केडार जलाशय से नहर द्वारा पानी लेंधरा छोटे और बरदुला के किसानों को लाभ मिले इसलिए लीलहर नाला उदवहन करने की मांग रखी।

रात 2 बजे से लाइन में किसान, सुबह 11 बजे खुला पेट्रोल पंप

लैलूँगा में डीजल संकट से हाहाकार, किसानों को सिर्फ 5 लीटर डीजल देकर भेजा जा रहा वापस

मूक पत्रिका/लैलूंगा=लैलूंगा क्षेत्र में डीजल संकट अब विकराल रूप लेता जा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि किसान और वाहन चालक रात 2 बजे से ही पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहे, लेकिन सुबह 11 बजे के बाद डीजल वितरण शुरू हो पाया।

डीजल की किल्लत से परेशान किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की मौजूदगी में लैलूंगा तहसीलदार की अगुवाई में डीजल वितरण कराया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद किसानों को मात्र 5 लीटर डीजल ही दिया जा रहा है। खेती-किसानी के इस महत्वपूर्ण समय में इतनी कम मात्रा मिलने से किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।

ट्रैक्टर चालक, पिकअप मालिक और ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में जुताई और कृषि कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कई किसानों ने आरोप लगाया कि पूरी रात जागकर लाइन में लगने के बाद भी पर्याप्त डीजल नहीं मिल पा रहा है।

खेती करें या लाइन में खड़े रहें?

डीजल संकट के चलते गांवों से आए किसानों की परेशानी साफदिखाई दी। कोई बोतल लेकर पहुंचा तो कोई ड्रम लेकर, लेकिन सबको सिर्फ 5 लीटर देकर वापस भेजा गया।

क्षेत्र में यह भी चर्चा तेज है कि आखिर डीजल की ऐसी नौबत क्यों आई? आम जनता और किसानों को सीमित मात्रा में डीजल दिया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर भारी वाहनों और मशीनों का संचालन लगातार जारी रहने पर सवाल उठने लगे हैं।

प्रशासन अलर्ट, लेकिन जनता बेहाल-

स्थिति को संभालने के लिए प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा। तहसीलदार की निगरानी में वितरण व्यवस्था कराई गई, लेकिन भीड़ और नाराजगी लगातार बढ़ती रही।

लैलूंगा में डीजल संकट अब सिर्फईंधन की कमी नहीं, बल्कि किसानों की चिंता और प्रशासनिक व्यवस्था की बड़ी परीक्षा बन चुका है।

पानी टंकी पर अडानी का प्रचार देख भड़के ग्रामीण

प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की उठाई मांग, मामला खरसिया विकासखण्ड के ग्राम पंचायत छोटे देवगांव का

मूक पत्रिका/रायगढ़= खरसिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत छोटे देवगांव में इन दिनों एक सरकारी और सार्वजनिक पानी टंकी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गांव की जिस पानी टंकी को आम जनता की सुविधा, पेयजल व्यवस्था और जनहित के उद्देश्य से बनाया गया था, उसी पर अब निजी कंपनी अडानी सीमेंट का बड़ा प्रचार-प्रसार किए जाने से लोगों का गुस्सा भड़क उठा है।

ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति पर इस तरह निजी कंपनी का नाम और विज्ञापन लगाना सीधे तौर पर सरकारी व्यवस्था और जनभावनाओं का अपमान है। गांव के लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर किस अधिकारी या विभाग की अनुमति से जनता की संपत्ति को कंपनी के प्रचार का माध्यम बना दिया गया? क्या अब सरकारी टंकियां, पंचायत भवन और अन्य सार्वजनिक संसाधन भी निजी कंपनियों की ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे?

स्थानीय नागरिकों के अनुसार गांव में कई मूलभूत समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। कहीं सडक़ जर्जर है, कहीं पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन इन समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय कंपनियों के प्रचार को बढ़ावा देता नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि यदि कंपनी को प्रचार ही करना है तो वह अपनी निजी जमीन और संसाधनों का उपयोग करे, सार्वजनिक संपत्तियों को क्यों कब्जे जैसा रूप दिया जा रहा है?

ग्रामीणों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि बिना ग्रामसभा और जनता की जानकारी के इस तरह का प्रचार किया गया। लोगों का कहना है कि यह केवल एक विज्ञापन नहीं, बल्कि धीरे-धीरे सार्वजनिक संपत्तियों पर निजी प्रभाव बढ़ाने की शुरुआत है। गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की तत्काल जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और सार्वजनिक पानी टंकी से कंपनी का प्रचार हटाया जाए।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा। अब पूरे क्षेत्र में एक ही सवाल गूंज रहा है

क्या जनता की संपत्तियों पर अब कंपनियों का राज चलेगा और प्रशासन तमाशबीन बना रहेगा?

कैदीमूड़ा में सरकारी जमीन पर बन रही कॉलोनी

गरीबों पे सितम रसूखदारों पर रहम !

कलेक्टर साहब के आदेश को भी ठेंगा, नाले पर अवैध कब्जे का भी लग रहा आरोप

मूक पत्रिका/रायगढ़= शहर के वार्ड क्रमांक 30 स्थित कैदीमूड़ा में शासकीय भूमि और सार्वजनिक नाले पर कथित अवैध कब्जे का मामला अब प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। मोहल्लेवासियों का आरोप है कि जहां प्रशासन गरीबों की झुग्गी-झोपड़ी हटाने के लिए पूरा सरकारी लाव-लश्कर लेकर पहुंच जाता है, वहीं रसूखदार कॉलोनाइजरों के सामने अधिकारियों की कार्रवाई ठंडी पड़ जाती है। दस्तावेजों के अनुसार 25 मार्च और 13 अप्रैल को एसडीएम, कलेक्टर और जनदर्शन में शिकायत दी गई थी। आवेदन में साफ लिखा गया कि खसरा नंबर 221-1-ख सहित शासकीय भूमि और सार्वजनिक नाले पर कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शिकायत में बारिश के दौरान संभावित जलभराव, बीमारी और जनहानि तक की आशंका जताई गई थी। बावजूद इसके, महीनों बीत जाने के बाद भी नजूल विभाग और नगर निगम की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई जमीन पर दिखाई नहीं दी।

इस मामले में कलेक्टर कार्यालय से निर्देश जारी हुए, एसडीएम ने भी नजूल अधिकारी को सीमांकन और कार्रवाई के आदेश भेजे, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूरा मामला फाइलों में ही दबा दिया गया। इस बीच कथित कॉलोनाइजर द्वारा पक्का निर्माण भी लगभग पूरा कर लिया गया।

मोहल्लेवासियों का कहना है कि 'अगर यही कब्जा किसी गरीब ने किया होता, तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन यहां बड़े लोगों का मामला है, इसलिए अधिकारी आंखे मूंदे बैठे हैं।

'वादे नहीं, समाधान चाहिए' - बस्तर मुद्दों पर कांग्रेस की पत्रकार वार्ता

आदिवासी अधिकार, हस्ष्ट, रोजगार, स्कूल बंदी और महंगाई के मुद्दे गूंजे

दैनिक मूक पत्रिका/ विक्रम ठाकुर /कांकेर :-कांकेर बस्तर के विकास, आदिवासी अधिकारों और स्थानीय समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को राजीव भवन कांकेर में पत्रकार वार्ता आयोजित कर केंद्र और राज्य सरकार के सामने कई अहम सवाल उठाए। पत्रकार वार्ता में बस्तर के विकास मॉडल, जल-जंगल-जमीन की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और उद्योगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश कांग्रेस सचिव जनक नन्दन कश्यप ने कहा कि बस्तर के लोग विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ऐसा विकास चाहते हैं जो आदिवासी संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय अधिकारों की रक्षा करते हुए हो। उन्होंने कहा कि लंबे समय से बस्तर की जनता विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन अब तक उनका स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से हस्ष्ट स्टील प्लांट के निजीकरण, हस्ष्ट मुख्यालय को जगदलपुर लाने, बंद हुए लगभग 2000 स्कूलों, आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा और खनिज संसाधनों के बाहरी कंपनियों को सौंपे जाने जैसे मुद्दे उठाए गए। कांग्रेस नेताओं ने सवाल किया कि बस्तर के संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। वार्ता के दौरान नंदराज पहाड़ की लीज, बस्तर के प्रत्येक गांव को एक करोड़ रुपये देने के वादे और लंबे समय से लंबित 50 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा गया। नेताओं ने कहा कि उद्योग स्थापित करने से पहले स्थानीय युवाओं के रोजगार और संभावित विस्थापन की स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को विशेष आर्थिक सहायता देने, निर्दोष आदिवासियों पर दर्ज मामलों की समीक्षा एवं वापसी तथा जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई की मांग भी उठाई गई।

भारी बारिश से क्षतिग्रस्त सड़क और पुल-पुलियों की मरम्मत, किसानों के धान खराब होने की घटनाओं और पेट्रोल, डीजल, गैस व खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर भी चिंता जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि आम जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है और अब केवल राजनीतिक वादे नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहती है। पत्रकार वार्ता में जिला महामंत्री उदय प्रकाश शर्मा बंटी, अनुसूचित जनजाति आयोग पूर्व सदस्य नितिन पोटाई, विजय यादव, मृदुला भास्कर, मुन्ना इसहाक अहमद, महिला अध्यक्ष भारती सलाम, शेष गजबिय, राजा ठाकुर, सत्यार्थ कारयत, शिवंकित श्रीवास्तव, प्रशांत सिन्हा सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सलाखों के पीछे भी शिक्षा की रोशनी

कांकेर जेल के बंदियों ने रचा नया इतिहास, 10वीं-12वीं में शानदार सफलता

दैनिक मूक पत्रिका/ विक्रम ठाकुर /कांकेर :- कांकेर जेल की ऊंची दीवारों के बीच भी शिक्षा की अलख लगातार जल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की मार्च-अप्रैल 2026 परीक्षा में कांकेर जिला जेल के बंदियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया कि सीखने की कोई उम्र और सीमा नहीं होती।

जेल अधीक्षक महेश कुमार एवं जिला ओपन समन्वय प्रभारी वाजिद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर निलेश महादेव क्षीरसागर एवं जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में बंदियों को 10वीं और 12वीं परीक्षा में शामिल कराया गया। परीक्षा शुल्क की व्यवस्था के साथ निःशुल्क पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई। जेल प्रशासन द्वारा शिक्षित बंदियों की मदद से नियमित कक्षाएं संचालित कर परीक्षा की तैयारी कराई गई, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया। इस वर्ष 10वीं में 17 एवं 12वीं में 8 बंदियों के परीक्षा फार्म भरे गए थे। 10वीं परीक्षा में 17 में से 12 बंदी उत्तीर्ण हुए, जिनमें 6 प्रथम श्रेणी, 5 द्वितीय श्रेणी और 1 तृतीय श्रेणी में पास हुआ। वहीं एक महिला बंदी ने 71 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की। 12वीं परीक्षा में शामिल 8 बंदियों में से 7 ने आरटीडी योजना के तहत चार विषयों में सफलता हासिल की, जबकि एक बंदी को पूरक की पात्रता मिली। खास बात यह रही कि 12वीं में शामिल सभी बंदी पूर्व में 10वीं परीक्षा भी जिला जेल कांकेर से उत्तीर्ण कर चुके हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि बंदियों को शिक्षा से जोड़कर समाज की मुख्यधारा में वापस लाने का प्रयास लगातार जारी है।

जिला पंचायत सदस्य बिनोद भारद्वाज ने उच्चभीठी सुशासन तिहार शिविर मे उठाया क्षेत्र का प्रमुख समस्याएं

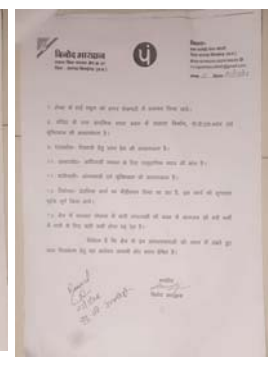

मूक पत्रिका/सारंगढ़-बिलाईगढ़। उच्चभीठी में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में जिला पंचायत सदस्य बिनोद भारद्वाज ने किसानों, ग्रामीणों एवं आमजन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने शिविर में उपस्थित अधिकारियों एवं कलेक्टर महोदया को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। सबसे पहले बिनोद भारद्वाज ने खेती-किसानी के लिए ट्रैक्टरों में डीजल की समस्या को लेकर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने कहा कि खेती का समय नजदीक है और किसानों को डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। साथ ही किसानों को समय पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के लिए समुचित व्यवस्था करने की मांग भी रखी। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों की मांगों एवं समस्याओं को लिखित रूप में कलेक्टर महोदया को सौंपते हुए सड़क, पेयजल, बिजली, सिंचाई सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के शीघ्र निराकरण की मांग की। इस दौरान बिनोद भारद्वाज ने नल-जल योजना में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा कि योजना का कार्य सही क्रम में नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पहले महानदी से कोसीर फिल्टरिंग मशीन तक व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए थी, उसके बाद गांव-गांव में पानी टंकी निर्माण और फिर घर-घर पानी सप्लाई का कार्य होना चाहिए था। लेकिन कार्य उल्टे क्रम में किए जाने के कारण कई घरों में नल कनेक्शन तो पहुंच गए हैं, परंतु पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा।

जिला पंचायत सदस्य ने क्षेत्र के सबसे बड़े गांव कोसीर को नगर पंचायत बनाने की मांग भी रखी। इसके साथ ही उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने तथा क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए महाविद्यालय खोलने की मांग प्रशासन के समक्ष रखी। उन्होंने आगे कहा कि सारंगढ़ क्षेत्र में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत लगभग 5000 हितग्राही अपात्र घोषित हुए हैं, जिनकी जांच कर पात्र महिलाओं को पुनः योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। साथ ही लगभग 15000 पेंशन प्रकरण बंद होने की बात कहते हुए उन्होंने जांच कर पात्र हितग्राहियों का पेंशन पुनः जोड़ने की मांग की, ताकि जरूरतमंद लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।

बिनोद भारद्वाज ने सुशासन तिहार शिविर में पहुंचे विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की समस्याओं को भी प्रशासन के समक्ष रखा और त्वरित समाधान की मांग की। शिविर में मौजूद अधिकारियों ने सभी मांगों एवं समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

93 लाख रूपये स्वीकृत तालाब में दूसरे तालाब जलकुंभी डंप, सीएमओं ने बरती सख्ती दी हटाने के निर्देश

शासन की योजना को कर रहे है बंटाधार घरघोड़ा नप का अदभुत कारनामा

मूक पत्रिका/रायगढ़= घरघोड़ा नगर पंचायत अपने नित नए कारनामे के चलते सुर्खियों में रहता है। भ्रष्टाचार की करस्तानी और नियमों के विपरीत कार्य करने के चलते एक साथ कई अधिकारी कर्मचारी के साथ पंचायत अधिकारी सीएमओ तक को निलंबित किया गया है। इस कार्रवाई से सीखने और सबक लेने के बजाए गैरजिम्मेदाराना रैव्य्या अपनाए हुए हैं आलम यह है कि वार्ड नंबर 10 में मौजूद छोटे मुड़ा तालाब में बगल में स्थित बगमुडा तालाब से जलकुंभी निकालकर डंप किया जा रहा है। इसकी भनक लगते सीएमओ ने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल संबधित अधिकारी को कचरा हटाने का निर्देश दिया है।

दरअसल घरघोड़ा नगर के वार्ड नंबर 10 और 12 में एक दूसरे से जुड़े हुए मौजूद है जिसमें एक तरफ बगमुडा है जबकि दूसरा तालाब छोटेमुडा है। दोनों ही तालाब अगल बगल में है। वर्तमान में दोनो तालाब के जीर्णोद्धार की योजना शासन के पास भेजा गया था, जिसमें बगमुड़ा तालाब के लिए 15 वे वित्त के तहत 19 लाख रूपये स्वीकृति मिला था। जबकि छोटे मुड़ा तालाब के लिए राज्य परिवर्तित योजना के अन्तर्गरत 2022-23 में 93लाख रूपये की स्वीकृति मिली है। वहीं बगमुड़ा तालाब में बड़े स्तर में यहां जलकुंभियो की मौजूदगी से तालाब बदहाली झेल रहा है। इससे कई तरह की व्यवहारिक परेशानियां लोगों को उठाना पड़ रहा है। जिसे देखते एक तालाब बगमुड़ा से जलकुंभी को हटाया जा रहा है। लेकिन उक्त तालाब से निकल गए जलकुंभियों को बगल में ही मौजूद छोटेमुडा तालाब मे तथा इर्दगिर्द एवं लैलूंगा रोड़ से जुड़े रेंगालबहरी मार्ग में डंप किया जा रहा है।यह आने वाले बारिश के मौसम में पानी के साथ वापस उसी तालाब में प्रवेश करेगा यह कहना गलत नही होगा। इसकी शिकायत जागरूक लोगों के द्वारा करते ही नगर पंचायत सीएमओ तत्काल हरकत में आई और संबधित अधिकारियों को फटकार लगाकर समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दी है। बताया जा रहा है कि सीएमओ ने

मौका मुआयना भी किया है। देखा जा रहा है यह एक तरह से स्वच्छता अभियान के धज्जियां भी उड़ा रहा है। बहरहाल नगर पंचायत अधिकारी की सख्ती से अधिकारी व कर्मचारियों में हलचल मचा दिया है।

केंद्रीय स्वच्छता टीम घरघोड़ा नगर में, ऐसे कैसे बढ़ेगा रेंकिंग- घरघोड़ा नगर पंचायत में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज नगर में एक ओर केंद्र सरकार की स्वच्छता टीम नगर के निरीक्षण और व्यवस्थाओं का आकलन करने पहुंची, वहीं दूसरी ओर नगर के बहुप्रतीक्षित तालाब के जल कुंभी का मसला सफाई में लापरवाही और नियमित मॉनिटरिंग की कमी सामने ला रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान केवल औपचारिक तैयारियां की जाती हैं, जबकि जमीनी स्तर पर सफाई व्यवस्था बदहाल रहती है।

दोनो तालाब के स्वीकृत कार्य और विवाद को ऐसे समझे- छोटेमुड़ा तलाब के गहरीकरण ओर सौंदर्यीकरण के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 2022-2023 में 93 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है,गहरीकरण का कार्य किया गया, ठेकेदारों के बिल 6.71 लाख रुपये प्रस्तुत भी हुआ। परंतु राजनीतिक नुराकस्सी में सितम्बर माह में नोटशीट पर यह लिख दिया गया कि अधीक्षण अभियंता बिलासपुर से जांच कराने टिप अंकित कर दिया गया।

ऐसे में भुगतान और अन्य कार्य रूक गया- जिसके कारण विगत 2 वर्ष से ऊपर हो चुके है भुगतान ना होने के कारण कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। बताया गया कि पक्ष रखा कि जब तालाब में पानी भर चुका है ऐसे में जांच सम्भव ही नही है। लेकिन कार्य लंबित है। इसी तरह वर्तमान में उक्त तलाब के बगल में स्थित बगमुड़ा तलाब में 15 वें वित्त के तहत 19 लाख रुपये के रिटर्निंग वाल पिचिंग के कार्य किया जाना है। उक्त कार्य को छोडक़र अब जल कुंभियो को निकाल कर छोटे मुड़ा तलाब में पाटा जा रहा है।

क्या कहते है पुष्पा खलखो, नगर पंचायत सीएमओ घरघोड़ा =मेरे द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया है। कुछ जलकुंभी निकालकर डंप किया गया था जिसे हटाने का निर्देश दिया गया है।

ठेकेदार लाखों के निर्माण कार्य में कर रहा सेंध मारी

देवरघटा नहर वाल निर्माण चड़ रहा भ्रष्टाचार का भेंट

जैजैपुर/मूक पत्रिका

दरअसल इन दिनों सक्ती ज़िले के जैजैपुर विकासखण्ड क्षेत्र अंतर्गत पराया पराया सभी नहर माइनरों पर मरम्मत कार्य एवं वाल निर्माण कार्यो का काम जोरों पर। जहाँ ठेकेदारों के द्वारा जमकर मनमाने तरीके से गूढ़वत्ताविहीन कार्य करा कर अपनी जेबे गर्म करने के फ़िराक़ में नजर आ रहे हैं। यहाँ बड़े ठेकेदार अपने दामन के दाग को बचाने के लिए स्थानीय रसूखदारों को अलग अलग माइनरों का काम पेटी में ठेका देकर जल संसाधन विभाग के नियम कायदों को ताक पर कर मनमाने तरीक़े से काम करा रहे है विभागीय अधिकारियों को ठेंगा दिखा रहे है। आपके जानकारी के लिए बता दें की जैजैपुर विकासखण्ड क्षेत्र में ऐसे कई नहर माइनरों में नाम मात्रा दिखावें युक्त कार्य कराए जा रहे है जो नहरों में पानी आने के बाद एक सीजन भी टिकना मुश्किल साबित होगा। ठेकेदार विभागीय अधिकारियों के नाक के नीचे खुलेआम विभागीय मापदंड का धज्जियां उड़ा कर निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे है। बता दें दरअसल पूरा मामला जिले के हसौद ब्लाक अंतर्गत देवरघाट नहर वाल निर्माण का है जहाँ लगभग 25-30 लाख रुपये के लागत से 300 मीटर का नहर के किनारों पर वाल निर्माण का कार्य गांव के ही स्थानीय व्यक्ति के द्वारा पेटी में ठेका लेकर कराया जा रहा है, जहां तय विभागीय माप का खुला अनदेखा कर निर्माण में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। तो वही वाल निर्माण में मानक उपयोगी सामग्री को दरकिनार कर मनमाने तरीके से निर्माण कार्य को सेंध लगा रहा है। विभागीय मापदण्डों को ठेकेदार दिखा रहा ठेंगा। जल संसाधन विभाग का छवि कर रहा धूमिल। एक मामला जैजैपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरघटा में सामने आया है जहाँ जल संसाधन विभाग द्वारा नहर की मिट्टी को रोकने के लिए वाल का निर्माण किया जा रहा है जिसमें जमकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। ठेकेदार एवं विभागीय इंजीनियर की मिलीभगत से केवल खानापूर्ति कर खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वाल निर्माण की लंबाई तीन सौ मीटर है और चौड़ाई डेढ़ मीटर होना चाहिए तो वही वाल निर्माण के नींव में एक एक फिट में सरिया लगना चाहिए जिसे ठेकेदार द्वारा तीन फीट में दो सरिया लगा रहा है, और वो सरिया भी जंग लगा हुआ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ वाल के फर्स कहीं कहीं चौड़ाई भी कम है। कंक्रीट में तराई भी नही किया जा रहा है इससे आप स्वयं ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाल कितना मजबूत होगा।नहर पार किनारे हो रहे वाल निर्माण कार्य अकुशल मजदूरों के सहारे हो रहा है जिनको मापदण्डों की कोई जानकारी ही नही है और विभागीय इंजीनियर भी अक्सर मौके से नदारद रहते हैं।जिसके कारण ठेकेदार मनमानी पूर्वक नियमों को अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य कर रहा है।

अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 4 वाहन जप्त

कलेक्टर के निर्देश पर खनिज अमले की सख्त कार्रवाई, 1.22 लाख रुपये अर्थदण्ड प्रस्तावित

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने हेतु कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 20 मई 2026 को खनिज अमले द्वारा बेमेतरा क्षेत्र में विशेष जांच एवं निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान रेत का अवैध परिवहन करते हुए 04 वाहनों को पकड़ा गया।खनिज विभाग की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहनों को जप्त कर थाना बेमेतरा की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ खड़ा कराया है। जांच के दौरान वाहनों के पास वैध दस्तावेज एवं परिवहन संबंधी अनुमति नहीं पाई गई, जिसके चलते अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित वाहन संचालकों के विरुद्ध खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23-ख के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में कुल 1 लाख 22 हजार रुपये की अर्थदण्ड राशि निर्धारित कर प्रशमन की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करने वालों के खिलाफनिरंतर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं शासन को राजस्व क्षति से बचाने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है। खनिज विभाग ने वाहन संचालकों एवं संबंधित कारोबारियों से अपील की है कि वे खनिज परिवहन संबंधी सभी नियमों का पालन करें तथा वैध अनुमति एवं दस्तावेजों के साथ ही परिवहन कार्य करें, अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ जन जागरण सेवा संस्थान ने उठाई प्रवासी मजदूरों एवं बच्चों की समस्याओं के लिए मांग

जैजैपुर/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ जन जागरण सेवा संस्थान के अध्यक्ष सुनील कुमार लहरे एवं बरदुली पंचायत के सरपंच-सचिव द्वारा ओड़ेकेरा में आयोजित सुशासन तिहार के दौरान कलेक्टर, एसडीएम एवं संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रवासी मजदूरों एवं उनके बच्चों को होने होने वाले समस्याओं को देखते हुए मांग की प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रवासी मजदूरों का सर्वे एवं पंजीयन अनिवार्य किया जाए,भूमि हिन् मजदूरों की सर्वे हो ताकि हर ग्राम पंचायत मे यह जानकारी उपलब्ध रहे कि कौन मजदूर किस राज्य में कार्य हेतु गया है। साथ ही मजदूर परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का रिकॉर्ड रखा जाए, जिससे शोषण, हिंसा एवं बंधुआ मजदूरी जैसी घटनाओं को रोका जा सके। संस्थान ने सक्ती जिले के करही गांव के 31 वर्षीय श्री रामनारायण बघेल की 17 दिसंबर 2025 को अन्य राज्य में हुई हत्या का उल्लेख करते हुए प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा हेतु मजबूत निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की।इसके साथ ही प्रवासी मजदूर परिवारों के स्कूल ड्रॉपआउट बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता, पुस्तकालय एवं ब्लॉक स्तर पर अध्ययन केंद्र शुरू करने की मांग भी प्रशासन के समक्ष रखी गई, ताकि मजदूर परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं सुरक्षित भविष्य मिल सके।

पीएम आवास योजना ग्रामीण में सख्तीः समय पर मकान पूरा नहीं करने वाले हितग्राहियों पर होगी वसूली कार्रवाई

जनपद पंचायत में 131 हितग्राहियों की 'पेशी', निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने के दिए सख्त निर्देश

बेमेतरा/मूक पत्रिका

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्वीकृत आवासों को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के लिए प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। जनपद पंचायत बेमेतरा अंतर्गत द्वितीय किस्त प्राप्त करने के बावजूद अपूर्ण पड़े आवासों को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) द्वारा जनपद पंचायत सभाकक्ष में विशेष समीक्षा बैठक सह 'पेशी' आयोजित की गई। प्रथम चरण की इस कार्रवाई में 131 हितग्राहियों को उपस्थित कराया गया। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-26 के तहत स्वीकृत 389 आवास ऐसे पाए गए हैं, जिनमें द्वितीय किस्त जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा है। इसे गंभीरता से लेते हुए जनपद सीईओ ने एक-एक हितग्राही से आवास निर्माण की प्रगति की जानकारी ली तथा निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। बैठक में सीईओ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को समय पर पक्का मकान उपलब्ध कराना है। शासन द्वारा राशि जारी किए जाने के बाद भी यदि हितग्राही निर्माण कार्य में लापरवाही बरतते हैं, तो इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी हितग्राहियों को अंतिम समय-सीमा के भीतर आवास पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। जनपद सीईओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित अवधि में आवास पूर्ण नहीं करने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध 'वसूली प्रकरण' (आरआरसी) दर्ज किया जाएगा। साथ ही सरकारी राशि का दुरुपयोग करने अथवा जानबूझकर निर्माण कार्य लंबित रखने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन द्वारा मैदानी अमले, रोजगार सहायकों एवं पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिदिन अपूर्ण आवासों की मॉनिटरिंग करें तथा हितग्राहियों को तकनीकी एवं व्यवहारिक सहयोग देकर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के बाद उन हितग्राहियों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है, जिन्होंने राशि प्राप्त होने के बाद भी आवास निर्माण कार्य में अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई थी।

टिमरलगा में उमेश को मिल रहा खनिज विभाग का खुला संरक्षण, 8 से 10 एकड़ का अवैध खदान, 4 हजार टन रोज बिक्री, 250 रुपया प्रति टन रेट,5 से 10 लाख का काला धंधा

खनिज अधिकारी बजरंग पैकरा और आर आई दीपक पटेल को लगातार सूचना देने पर भी खदान को देखना भी जरूरी नहीं समझते

सारंगढ़ बिलाईगढ/मूक पत्रिका

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बहुत से हिस्सों को प्रकृति ने अपने अमूल्य खनिज संपदा से भरपुर और एक सुंदर सा पर्यावरण समस्त जीवों को तोहफे में दिया है। सारंगढ़ कुछ हिस्सों के (खनिज क्षेत्रों के अंतर्गत) पंचायत में खनिज संपदा काफ़ी प्रचूर मात्रा में है। जिसका लाभ पंचायतों से लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को सीधा-सीधा मिलता है। जो लीज धारक से रॉयल्टी का 30त्न अतिरिक्त टैक्स के रूप में सरकार और पंचायतों को वैध खनिज खनन से ष्ठरूस्न फंड के रूप में जमा होता है। यह पैसा सिर्फ खनन से प्रभावित गांवों और क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति और आम जनजीवन को प्रभाव से बचाने के लिए सहयोग के रूप में खर्च किया जाता है। जैसे सड़क, स्कूल, पानी टंकी, आंगनबाड़ी इत्यादि जिससे खनन प्रभावित क्षेत्र को सहयोग के साथ कुछ लाभ मिल जाता है। किंतु खनन माफ़ियाओं के द्वारा अवैध खनन करके खनिज विभाग और पर्यावरण विभाग से लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व का सीधा-सीधा नुकसान पहुंचाया जाता है। यह राजस्व कर के रूप में लाखों-करोड़ तक का कारोबार होता है। वर्तमान समय में ग्राम पंचायत टिमरलगा में उमेश पटेल के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित नियमों की धज्जियां उड़ते हुए अवैध खदान जोरों से चला रहा है। जिससे सरकार को प्रति माह लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और जिम्मेदार अधिकारी इस पर अंकुश लगाने की बजाय उसमें अपना कमिशन ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही उमेश पटेल जैसे कितने ही खनन माफ़ियाओं ने जिले में अपने धनबल, राजनीतिक प्रभावों और दबंगई से अपने अवैध गतिविधियों का साम्राज्य बनाए बैठे हैं जिस पर खनिज विभाग के अधिकारी अंकुश नहीं लग पा रहे हैं और उन्हीं के सहयोग से अपना अनैतिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे की राज्य सरकार के आर्थिक व्यवस्था क्या होगा?? हर महीने राज्य सरकार अपनी करोड़ों के राजस्व के संपत्ति का नुकसान इन भ्रष्ट विभागीय अफ़्सरों की वजह से कर रही है जो अपने अनैतिक लाभ की वजह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज जिले में तमाम जगह पर अवैध खनन का कारोबार जोरों शोरों से हो रहा है उस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रही है और लगातार यह सिलसिला और भी क्यों बढ़ता जा रहा है???

जिसका संपूर्ण जवाबदारी खनिज विभाग को है लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी इस पर एक्शन लेना तो दूर अपने ऑफ़िस से निकलना भी जरूरी नहीं समझते? इसके चलते आज जिला भर में ताबड़ तोड़ अवैध खदान संचालित हो रहा है। जोकि ऑन द स्पॉट देखा जा सकता है। टिमरलगा में अवैध खनन के सरताज उमेश भाऊ की कमाई व खनन के कुछ समीकरण सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत टिमरलगा में उमेश पटेल को अब पुष्पा भाऊ के नाम से जाने जाते हैं। बता दे कि उमेश पटेल के अवैध खदान पर एक साथ दस दस पोकलेन मशीन से अवैध खनन किया जाता है। इन पत्थरों को गुड़ेली टिमरलगा के क्रशरों में पत्थर को बेचा जाता है, पत्थर बेचने के लिए लगभग 20 से 25 हाईवा का इस्तेमाल किया जाता है। एक हाईवे पर लगभग 30 से 35 टन पत्थर का वजन आता है वही एक टन पत्थर भाव 250 क्रेशर संचालक को प्रति टन के हिसाब से देना पड़ता है उसे हिसाब से अगर आंकड़ा लगाया जाए तो प्रतिदिन का लगभग 4000 टन और 8 से 10 लख रुपए का कमाई सामने आई है। सोचिए जरा इतना बड़ा अवैध कांड बिना अधिकारियों के सहमति के बिना संभव है कैसे???

बिना लाइसेंस उर्वरक भंडारण पर डभरा के ग्राम बिरहाभांठा में की गई कार्रवाई, 60 बोरी नीमलेपित यूरिया जब्त

सक्ती/मूक पत्रिका

कलेक्टर अमृत विकास तोपनो एवं उप संचालक कृषि तरुण कुमार प्रधान के मार्गदर्शन में उर्वरक की असामान्य बिक्री, कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकने के लिए जिला एवं विकासखंड स्तरीय दल द्वारा लगातार निगरानी एवं जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कृषि विभाग जिला सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार विगत दिवस को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर विकासखंड स्तरीय दल द्वारा विकासखंड डभरा के ग्राम बिरहाभांठा में बाबूलाल उरांव पिता परशुराम उरांव के घर पर छापामार कार्रवाई की गई। जांच के दौरान बिना वैध दस्तावेज के 60 बोरी (2.700 मीट्रिक टन) नीमलेपित यूरिया का भंडारण पाया गया। उक्त मामले में संबंधित कृषक से क्रय बिल एवं जमीन संबंधी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर प्रथम दृष्ट्या उर्वरक की कालाबाजारी कर किसानों को अधिक दर पर बिक्री किए जाने की आशंका पाई गई। इसके फलस्वरूप उर्वरक नियंत्रण आदेश में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उर्वरक निरीक्षक विकासखंड डभरा द्वारा 60 बोरी नीमलेपित यूरिया को जब्त कर संबंधित व्यक्ति को स्पष्टीकरण जारी किया गया। जब्त उर्वरक को ग्राम कोटवार गंगाधर चौहान की सुपुर्दगी में सौंपा गया। कृषि विभाग द्वारा विकासखंड के समस्त उर्वरक विक्रेताओं, भंडारणकर्ताओं एवं कृषकों से अपील की गई है कि बिना वैध लाइसेंस के उर्वरकों का भंडारण, परिवहन अथवा विक्रय न करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से उर्वरकों का भंडारण कर कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

किसानों से भी आग्रह किया गया है कि वे अधिकृत विक्रेताओं से ही उर्वरक क्रय करें तथा पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना विकासखंड कृषि कार्यालय में देने की अपील की गई है। कार्रवाई के दौरान विकासखंड डभरा के उर्वरक निरीक्षक आर.के. पटेल, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हेमसागर पटेल, हल्का पटवारी हरिशंकर पटेल एवं ग्राम कोटवार उपस्थित रहे।

टेट विसंगति को लेकर सहायक शिक्षक फेडरेशन का सीएम से संवाद, समाधान का मिला भरोसा

लाखों टेट प्रभावित शिक्षकों की आवाज़ सीएम तक पहुँची

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के लाखों टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) से प्रभावित शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान फेडरेशन पदाधिकारियों ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कार्यरत शिक्षकों से जुड़ी टेट विसंगतियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बसंत कौशिक एवं राजीव नयन शुक्ला ने किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में लाखों सहायक शिक्षक एवं समग्र शिक्षक वर्षों से शासकीय सेवा दे रहे हैं, किंतु टेट से जुड़ी कुछ तकनीकी विसंगतियों एवं नियमों के कारण उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे शिक्षक एवं उनके परिवार लंबे समय से मानसिक व आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं।मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता से सुना और फेडरेशन को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार शिक्षकों की जायज मांगों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि टेट से प्रभावित लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगामी समय में केंद्र सरकार के समक्ष भी छत्तीसगढ़ की ओर से इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा तथा केंद्र एवं राज्य स्तर पर सकारात्मक समाधान निकालने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री से मिले इस ठोस और सकारात्मक आश्वासन के बाद फेडरेशन पदाधिकारियों एवं प्रदेश के लाखों शिक्षकों में न्याय की नई उम्मीद जगी है। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बसंत कौशिक एवं राजीव नयन शुक्ला ने कहा कि यह मुलाकात छत्तीसगढ़ के टेट प्रभावित शिक्षकों के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर फेडरेशन की ओर से राजीव नंदनी वर्मा, राजू टंडन सहित बड़ी संख्या में शिक्षक प्रतिनिधि एवं फेडरेशन के साथी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित। संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।